

आन्दोलन
अशुद्ध के विरुद्ध

KEDIA™
Pavitra

FIXED
PRICE

250 g
MRP ₹ 250



विश्व की सर्वोत्तम हल्दी
7-12% CURCUMIN वाली
CRYOGENIC GRINDING से बनी
भारत की एकमात्र लाकाडोंग हल्दी पाउडर
(साधारण हल्दी से 4 गुना ज्यादा करक्यूमिन)

क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग से बने प्रोडक्ट्स
लाकाडोंग हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर

ब्लेंडेड मसाले

किचन किंग मसाला • गरम मसाला • सब्जी मसाला • शाही पनीर मसाला
दाल मखनी मसाला • राजमा मसाला • चना मसाला • पाव भाजी मसाला • सांभर मसाला
चाट मसाला • छाछ मसाला • रायता मसाला • जलजीरा मसाला • पोहा मसाला
चाय मसाला • अमचूर पाउडर • हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट • तूफानी हींग

लाकाडोंग हल्दी पाउडर

मेघालय के लाकाडोंग की पहाड़ियों में उगाई गई प्रीमियम GI TAGGED हल्दी से बना

कॉल लगाओ, गाड़ी बुलाओ
1800-120-2727

For joining us as Distributor or Business Development Officer
Email ID: bdm@kediapavitra.com | Call: +91 76888-66333



www.rera.rajasthan.gov.in | RERA No. RAJ/P/2023/2387

FIXED
PRICE

₹4000/- में फ्लैट!

NO
MIDDLE
MEN



वैशाली की रेट
12000/- Sq. Ft.

8 मिनट की दूरी की रेट
4000/- Sq. Ft.

8 मिनट में
8000/- Sq. Ft. की बचत

अब हर महीने रेट बढ़ेगी

PRODUCT TYPE	UNIT TYPE	SIZE	PRESENT RATE	31 MAY 2026	30 JUNE 2026	31 JULY 2026	31 AUG. 2026	30 SEPT. 2026	31 OCT. 2026	30 NOV. 2026	30 DEC. 2026
WALK-UP APARTMENT	2 BHK (GF)	1350 Sq Ft	65 Lacs	66 Lacs	68 Lacs	70 Lacs	72 Lacs	74 Lacs	76 Lacs	78 Lacs	80 Lacs
	3 BHK (SF)	1900 Sq Ft	75 Lacs	76 Lacs	78 Lacs	80 Lacs	82 Lacs	84 Lacs	86 Lacs	88 Lacs	90 Lacs
	3 BHK (FF)	1900 Sq Ft	80 Lacs	82.5 Lacs	85 Lacs	87.5 Lacs	90 Lacs	92.5 Lacs	95 Lacs	97.5 Lacs	1 Cr
KOTHI	3 BHK BIG	2000 Sq Ft	1.05 Cr	1.075 Cr	1.10 Cr	1.125 Cr	1.15 Cr	1.175 Cr	1.20 Cr	1.225 Cr	1.25 Cr
	4 BHK BIGGER	2325 Sq Ft	1.26 Cr	1.29 Cr	1.32 Cr	1.35 Cr	1.38 Cr	1.41 Cr	1.44 Cr	1.47 Cr	1.50 Cr
	4 BHK BIGGEST	3200 Sq Ft	1.60 Cr	1.65 Cr	1.70 Cr	1.75 Cr	1.80 Cr	1.85 Cr	1.90 Cr	1.95 Cr	2 Cr

KEDIA®

1800-120-2323

info@kedia.com
www.kedia.com
78770-72737



SCAN QR FOR
• LOCATION
• ROUTE MAP
• SITE 360 TOUR
• E-BROCHURE
• WALKTHROUGH

*TBC Apply

विचार बिन्दु

सत्प्रथम इस लोक की चिंतामणि नहीं उनके अध्ययन से सारी कुचिंताएं मिट जाती हैं। संशय पिशाच भाग जाते हैं और मन में सद्भाव जागृत होकर परम शांति प्राप्त होती है। -अज्ञात

पेंशन के लिए पैसा नहीं, मुफ्त की रेविडियों के लिए खजाना खुला है - राजस्थान के विश्वविद्यालय पेंशनरों के साथ अन्याय कब तक?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा- पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचो, 'लाइकी बहन' जैसी योजनाएं बंद करो। अदालत का यह आदेश केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा। पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, 43000 करोड़ रु. की लाइकी बहन जैसी योजना बंद करें-बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई ने स्पष्ट और सख्त शब्दों में कहा है कि फंड की कमी का बहाना बनाकर सरकार या नगर निगम प्रशासन पेंशन और बकाया लाभों का भुगतान टाल नहीं सकता। अदालत ने यहां तक कह दिया कि अगर पैसे नहीं हैं तो गैर-जरूरी योजनाएं बंद करें या दफ्तरी की संपत्ति बेचें, लेकिन कर्मचारियों को उनका हक जरूर दें।

यह टिप्पणी सातवें वेतन आयोग लागू होने से पेंशनरों के सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। मुंबई नगर निगम के शिक्षा विभाग में कार्यरत रही एक महिला कर्मचारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा तब खटखटाया, जब सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन और अन्य वैधानिक लाभ नहीं मिले। बार-बार आग्रह के बावजूद नगर निगम और सरकार की ओर से केवल फंड की कमी का हवाला दिया जा रहा था, जिससे उनका जीवनयापन कठिन हो गया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासन की दोहरी नीति पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब अतिरिक्त आयुक्तों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार पूरा वेतन मिल सकता है, तब शिक्षकों और कर्मचारियों के मामले में अचानक फंड की कमी क्यों सामने आ जाती है। कोर्ट ने कहा कि जब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का समय आ चुका है, तब भी सातवें वेतन आयोग लंबित रखना गंभीर लापरवाही है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार के पास सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन देने के लिए धन नहीं है, तो उसे 'लाइकी बहन' जैसी योजनाएं बंद करने पर विचार करना चाहिए। कर्मचारियों का वेतन और पेंशन कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि उनका कानूनी अधिकार है।

यह टिप्पणी राजस्थान सरकार और यहां के सभी विश्वविद्यालयों के लिए आईना है। यह खबर राजस्थान के विश्वविद्यालय पेंशनरों का दर्द बयान करती है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के पेंशनर 12 दिन से घरने पर हैं। 42.6 डिग्री तापमान में न छाया, न पानी की व्यवस्था। नतीजा-बार-बार बुजुर्ग बहोश होकर मिर पड़े। ओआरएस और दवाइयों से प्राथमिक उपचार करना पड़ा। पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रो. रामनिवास शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि किसी को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार होंगी।

सवाल यह है-नौबत यहां तक क्यों आई? विश्वविद्यालय की सालाना आय 76 करोड़ है, जबकि खर्च 121 करोड़। यानी हर साल 45 करोड़ का घाटा। 1,475 पेंशनरों को सालाना 105 करोड़, यानी हर महीने 8.75 करोड़ रुपये पेंशन देने की पड़ रही है। पिछले 8 वर्षों में 16 बार आंदोलन हो चुके हैं, पिछले वर्ष जुलाई में 92 दिन लगातार आंदोलन हुआ। फिर भी हर दूसरे महीने घरना देना पड़ रहा है।

अच्छी बात है कि गरीबों को राहत मिले, लेकिन क्या यह राहत उन लोगों का हक मारकर दी जा रही है जिन्होंने जीवन भर सेवा की? कृषि विश्वविद्यालयों में स्थिति और भी गंभीर है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में 22 महीनों की पेंशन बकाया है। महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत के स्थान पर केवल 12 प्रतिशत दिया जा रहा है, वह भी अदालत के हस्तक्षेप के बाद। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही, सातवें वेतन आयोग का एरियर लंबित है, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही, कम्प्यूटेड पेंशन पर रोक है।

अच्छी बात है कि गरीबों को राहत मिले, लेकिन क्या यह राहत उन लोगों का हक मारकर दी जा रही है जिन्होंने जीवन भर सेवा की? कृषि विश्वविद्यालयों में स्थिति और भी गंभीर है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में 22 महीनों की पेंशन बकाया है। महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत के स्थान पर केवल 12 प्रतिशत दिया जा रहा है, वह भी अदालत के हस्तक्षेप के बाद। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही, सातवें वेतन आयोग का एरियर लंबित है, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही, कम्प्यूटेड पेंशन पर रोक है।

विडंबना यह है कि वर्तमान कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को 12-42 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। यह केवल वित्तीय संकट नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता का प्रमाण है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह पैसा आता कहाँ से है? यह पैसा इमानदार टैक्सपेयर की जेब से आता है-वह मध्यम वर्ग जो सुबह 9 से शाम 6 तक मेहनत करता है, इनकम टैक्स देता है, जोएसटी देता है। जब सरकार उसी पैसे से मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, नकद सहायता बांटती है, तो विकास के कार्यों में कटौती होती है। सड़कें टूटती हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, नहरों में पानी नहीं-क्योंकि पैसा रेविडियों बांटने में खर्च हो रहा है। क्या यह टैक्सपेयर के साथ ठगवट नहीं है? उसने टैक्स इसलिए दिया था कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे-न कि वोट बैंक बनाने के लिए पैसा बांटा जाए। मुफ्तखोरी समाज को आलसी बना रही है। युवा वर्ग में यह मानसिकता बन रही है कि सरकार देगी तो काम क्यों करें? यह राष्ट्र की उत्पादकता पर सीधा प्रहार है। स्वाभिमान से काम करके खाने की संस्कृति खत्म हो रही है और सरकार पर निर्भरता बढ़ रही है।

समाधान भी स्पष्ट है। सबसे पहले, पेंशन और वेतन को प्राथमिकता दी जाए-यह कोई नया नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है। दूसरे, फिजूलखर्ची पर रोक लगे-यदि पेंशन के लिए पैसा नहीं है तो गैर-जरूरी योजनाएं बंद हों। तीसरे, जवाबदेही तय हो-विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाए। उनके खर्चों में कटौती कर पेंशन दी जा सकती है।

अब सरकार को तय करना है-लोकप्रियता या न्याय? वोट बैंक या राष्ट्र निर्माण? मुफ्तखोरी या स्वाभिमान? बॉम्बे हाईकोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है। अब राजस्थान सरकार और विश्वविद्यालयों को निर्णय लेना है कि वे कुर्सी-टेबल बेचेंगे या पेंशनरों के आंसू पोंछेंगे। क्योंकि जिस देश में गुरु भूख के कगार पर हो और मुफ्त की रेविडियां बांटी जाएं, उस देश का भविष्य अंधकारमय होता है।

अंततः यह केवल आर्थिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों का प्रश्न है। जिस समाज में अपने शिक्षकों और वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़े, वहां विकास अधूरा रह जाता है। समय आ गया है कि सरकार यह तय करे-क्या वह रेवडी संस्कृति को बढावा देगी या उन लोगों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करेगी, जिन्होंने जीवन भर राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है।

-अतिथि सम्पादक,

प्रो. पी. सी. कंठालिया,

पूर्व विभागाध्यक्ष एवं मुख्य मुद्रा वैज्ञानिक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रो. विश्वविद्यालय, उदयपुर

लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाना और को परिसीमन - राज्यों के शक्ति संतुलन को बचाकर न्यायसंगत प्रतिनिधित्व कैसे हो



महावीर सिंह

16,17 अप्रैल 26 को लोकसभा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बहस हुई। अवसर था नारी शक्ति को लोकसभा, विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व देना। वैसे तो महिलाओं के लिए ऐसा संविधान संशोधन पहले किया जा चुका था किंतु राम, जाने उसे तत्काल लागू क्यों नहीं किया गया था? क्या उसी संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं किया जा सकता था? लेखक के अनुसार किया जा सकता था, कोई बाधा नहीं थी। इसे अनावश्यक रूप से जनगणना और डिलिमिटेशन से जोड़ा गया।

ऐसा क्यों किया गया? इस पर संसद में व्यापक चर्चा हो चुकी है। उसे दोहराने का कोई अर्थ नहीं होगा। सत्ता पक्ष महिलाओं का बड़े पैमाने पर समर्थन चाहता है और इस की आड़ में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों को मनमर्जी से पुनर्गठित करना चाहता था, ऐसा लगभग सम्पूर्ण विपक्ष का कहना था। निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन में, यदि आयोग निष्पक्षता से काम नहीं करे तो सत्ता पक्ष की इच्छाओं के अनुसार पटवार मंडलों, गिरदारण हलकों को इस ढंग से निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ और हटा सकता है जो एक बार तो सत्तापक्ष का पलड़ा भारी कर ही सकता है।

परिसीमन यानी लोकसभा और विधानसभा सीटों का फिर से बंटवारा 2026 के बाद का सबसे बड़ा लोक-तुल्यता खोजनाओं के लिए खजाना हमेशा खुला रहता है, लेकिन जिन शिक्षकों ने 35-40 साल तक राष्ट्र निर्माण किया, उनकी पेंशन के लिए फंड की कमी का रोना रोया जाता है। राज्य में अनेक योजनाएं चल रही हैं-लाइको प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, युवा स्वरोजगार योजना, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुफ्त बिजली योजना-इन पर हर साल 40-50 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय पेंशनरों के लिए 550 करोड़ रुपये नहीं हैं।

अच्छी बात है कि गरीबों को राहत मिले, लेकिन क्या यह राहत उन लोगों का हक मारकर दी जा रही है जिन्होंने जीवन भर सेवा की? कृषि विश्वविद्यालयों में स्थिति और भी गंभीर है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में 22 महीनों की पेंशन बकाया है। महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत के स्थान पर केवल 12 प्रतिशत दिया जा रहा है, वह भी अदालत के हस्तक्षेप के बाद। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही, सातवें वेतन आयोग का एरियर लंबित है, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही, कम्प्यूटेड पेंशन पर रोक है।

विडंबना यह है कि वर्तमान कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को 12-42 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। यह केवल वित्तीय संकट नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता का प्रमाण है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह पैसा आता कहाँ से है? यह पैसा इमानदार टैक्सपेयर की जेब से आता है-वह मध्यम वर्ग जो सुबह 9 से शाम 6 तक मेहनत करता है, इनकम टैक्स देता है, जोएसटी देता है। जब सरकार उसी पैसे से मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, नकद सहायता बांटती है, तो विकास के कार्यों में कटौती होती है। सड़कें टूटती हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, नहरों में पानी नहीं-क्योंकि पैसा रेविडियों बांटने में खर्च हो रहा है। क्या यह टैक्सपेयर के साथ ठगवट नहीं है? उसने टैक्स इसलिए दिया था कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे-न कि वोट बैंक बनाने के लिए पैसा बांटा जाए। मुफ्तखोरी समाज को आलसी बना रही है। युवा वर्ग में यह मानसिकता बन रही है कि सरकार देगी तो काम क्यों करें? यह राष्ट्र की उत्पादकता पर सीधा प्रहार है। स्वाभिमान से काम करके खाने की संस्कृति खत्म हो रही है और सरकार पर निर्भरता बढ़ रही है।

समाधान भी स्पष्ट है। सबसे पहले, पेंशन और वेतन को प्राथमिकता दी जाए-यह कोई नया नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है। दूसरे, फिजूलखर्ची पर रोक लगे-यदि पेंशन के लिए पैसा नहीं है तो गैर-जरूरी योजनाएं बंद हों। तीसरे, जवाबदेही तय हो-विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाए। उनके खर्चों में कटौती कर पेंशन दी जा सकती है।

अब सरकार को तय करना है-लोकप्रियता या न्याय? वोट बैंक या राष्ट्र निर्माण? मुफ्तखोरी या स्वाभिमान? बॉम्बे हाईकोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है। अब राजस्थान सरकार और विश्वविद्यालयों को निर्णय लेना है कि वे कुर्सी-टेबल बेचेंगे या पेंशनरों के आंसू पोंछेंगे। क्योंकि जिस देश में गुरु भूख के कगार पर हो और मुफ्त की रेविडियां बांटी जाएं, उस देश का भविष्य अंधकारमय होता है।

अंततः यह केवल आर्थिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों का प्रश्न है। जिस समाज में अपने शिक्षकों और वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़े, वहां विकास अधूरा रह जाता है। समय आ गया है कि सरकार यह तय करे-क्या वह रेवडी संस्कृति को बढावा देगी या उन लोगों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करेगी, जिन्होंने जीवन भर राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है।

-अतिथि सम्पादक,

प्रो. पी. सी. कंठालिया,

पूर्व विभागाध्यक्ष एवं मुख्य मुद्रा वैज्ञानिक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रो. विश्वविद्यालय, उदयपुर

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की सदस्य संख्या तय की गई है। प्रथम लोकसभा के लिए, 1950 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर औसतन एक सीट प्रति 7,20,000 जनसंख्या का आधार लिया गया था। पूरे देश के लिए कुल 401 निर्वाचन क्षेत्र बने और इस आधार पर पहला सार्वभौम वयस्क मतधिकार वाला चुनाव हुआ। 1951 जनगणना के आधार पर हुए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीटें बढ़कर 494 हो गईं। 1963 में परिसीमन आयोग ने 1961 जनगणना के आधार पर और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन सीटें बढ़कर 522 हुईं। 1971 जनगणना के बाद सीटें बढ़कर 543 हुईं और यही संख्या है।

1976 के 42वें संशोधन ने 1971 जनगणना के आधार पर सीटों का राज्य-वार आवंटन फ्रीज कर दिया। इसे 2001 में 84वें संशोधन द्वारा 2026 तक बढ़ाया गया। 2002 Delimitation ने सीटों की कुल संख्या नहीं बदली, सिर्फ सीमाएं समायोजित कीं। यह भी याद रखना होगा कि भारतीय संविधान में दूसरे संशोधन, 1952 की के द्वारा 'not less than one member for every 750,000 of the population and' हटा दिया गया और इस प्रकार 7,50,000 की अधिकतम सीमा पूरी तरह हटा दी गई। केवल 5,00,000 की कम से कम जनसंख्या सीमा बनी रही जिसे भी बाद के संशोधनों में हटा दिया।

वर्तमान में कुछ प्रांतों की सीटों की स्थिति पर विचार करें। लोकसभा में 543 में से उत्तर प्रदेश के 80, बिहार 40, महाराष्ट्र 48 सीटें, तमिलनाडु 39, केरल 20 सीटें और राजस्थान में उत्तर प्रदेश के 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, केरल 9 सदस्य हैं। आंध्र का है कि 2026 के बाद अगर केवल जनसंख्या आधार माना तो बड़-बिहार की लोकसभा सीटें 200 पर कर सकती है। तमिलनाडु-केरल की सीटें अनुपातिक रूप से घटेंगी। इससे जिन राज्यों ने परिवार नियोजन लागू किया, उन्हें 'सजा' मिलेगी और राज्यों के केंद्र के तथा आपस में राज्यों के बीच अविश्रवास बढ़ेगा। देश के संविधान में उल्लेखित संघवाद की भावना क्षीण होगी।

संविधान क्या कहता है अनुच्छेद 81: लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में होगा। अनुच्छेद 82: हर जनगणना के बाद परिसीमन होना है, पर 42वां और 84वां संशोधन कर 2026 तक इसे टाल दिया गया। अनुच्छेद 80: राजस्थान राज्यों का सदस्य है, पर सदस्य संख्या जनसंख्या पर आधारित है। संविधान 'जनसंख्या' और 'संघीय संतुलन' दोनों की बात करता है। इसलिए इस गंभीर प्रश्न पर अत्यंत गंभीरता पूर्वक मनन किया जाकर देश हित में निर्णय आवश्यक है। जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मान्यता भी मिले और राज्यों के बीच संघीय संतुलन को कायम रहे। किसी राज्य को यह नहीं लगाना चाहिए कि उसे प्रगतिशील नीतियों के सफल क्रियान्वयन करने की सजा मिल रही है। इसके साथ ही संघीय आय व राजस्व में पिछड़े, विशेष समस्याओं वाले राज्यों का उचित खयाल रखा जाए।

इस संबंध में कई प्रस्ताव विभिन्न राजनीतिक दलों व नेताओं, स्वतंत्र विचारकों, संविधान के ज्ञाताओं के विचार संसद में, समाचार पत्रों में, टीवी चैनल पर सामने आए हैं। एक प्रस्ताव है ---राज्यसभा में हर राज्य से 5,7 सांसद हों अर्थात् राज्य सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार न हो। राज्य सभा 'राज्यों का सदन' है। उदाहरणार्थ अमेरिका की सीनेट में हर राज्य से 2 सदस्य होते हैं, चाहे कैलिफोर्निया हो या अलास्का। इससे छोटे राज्यों को संघ में बराबरी मिलती है।

क्या भारत में इस पर, किसी अन्य प्रकार से विचार किया जा सकता है? एक आधार हो सकता है, 250 सीटों में से हर राज्य को 1 या 2 या 3 सीटें कुल 36/72/108 सीटें मिलें। वर्तमान संख्या 350 में से बाकी 214 /178/142 सीटें क्षेत्रफल 25%, राजस्व योगदान 25%, मानव विकास सूचकांक 25%, अनुसूचित क्षेत्र/सीमावर्ती 25% के आधार पर बांटी जा सकती है। किसी राज्य विशेष के लिए अधिकतम सीमा 5 सदस्य प्रति राज्य रखी जा सकती। इस से सिक्किम, गोवा, नॉर्थ-ईस्ट की आवाज मजबूत होगी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र को भी जनसंख्या प्रदान की 'सजा' नहीं मिलेगी। हां, यह अवश्य है कि UP, बिहार जैसे राज्यों को लोवा कि उनके प्रदेश का प्रतिनिधित्व घटा।

एक अन्य विकल्प यह हो सकता है कि संविधान संशोधन कर राज्यसभा को योजनाओं पर पूर्ण बहस व सूशोधनों का अधिकार दिया जाए। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधेयक लोकसभा में ही पास होता है। राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है।

संविधान का अनुच्छेद 110 बदले बिना भी राज्य सभा में संसदीय समिति बनाकर को सभी 500 करोड़ से ऊपर की योजनाएं पहले राज्यसभा में विस्तृत बहस के लिए भेजी जा सकती हैं। इस से जिन राज्यों का असर राज्यों पर पड़ता है, उन पर राज्यों के सदन को पूर्व-समीक्षा का अधिकार मिले। इससे संघीय भावना बढ़ेगी। संसामुक्त बंटवारे में जित आयोग की सिफारिश पर राज्यसभा में बहस व समर्थन अनिवार्य हो।

लोकसभा सीटों का राज्यों में वितरण के लिए भी सिर्फ जनसंख्या से हटकर 'बहु-सूचकांक फॉर्मूला' अपनाया जा सकता। यदि केवल जनसंख्या को आधार मानें तो 10,15,20 लाख की जनसंख्या पर एक लोक सभा सीटें निर्धारित हो तो संख्या इस प्रकार हो सकती है:-1420, 940, 720।

एक प्रस्ताव के अनुसार, 2026 के जनसंख्या के आधार पर संविधान में उल्लेखित कुल 543 की सदस्य संख्या का 50% अथवा अन्य कोई प्रतिशत जो संसद तय करे, उसके अनुसार, एक व्यक्ति एक वोट के अनुसार रखी जा सकती है। लोकसभा में 10% प्रतिनिधित्व क्षेत्रफल के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जिस से राजस्थान जैसे बड़े पर कम घनत्व वाले राज्यों का महत्व मिलेगा।

अन्य बिंदु जिन का लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर ध्यान रखा जा सकता है, वे यह हो सकते हैं:- राजस्व एकत्रीकरण:- ---महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु को जोएसटी-आयकर में 15% ज्यादा देते हैं, उन्हें महत्व मिलेगा। विकास व्यय गती:- पिछले 10 साल में पूंजीगत व्यय के आधार पर अर्थात् राज्य में पैसा जमीन पर लगाया उसके आधार पर मानव विकास सूचकांक अर्थात् HDI + पिछड़ापन भी पैमाने में हो। केरल का 3% ऊंचा है तो उसे इनाम मिलना चाहिए। बिहार, झारखंड का कम है

टीवी चैनल पर सामने आए हैं।

एक प्रस्ताव है ---राज्यसभा में हर राज्य से 5,7 सांसद हों अर्थात् राज्य सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार न हो। राज्य सभा 'राज्यों का सदन' है। उदाहरणार्थ अमेरिका की सीनेट में हर राज्य से 2 सदस्य होते हैं, चाहे कैलिफोर्निया हो या अलास्का। इससे छोटे राज्यों को संघ में बराबरी मिलती है।

क्या भारत में इस पर, किसी अन्य प्रकार से विचार किया जा सकता है? एक आधार हो सकता है, 250 सीटों में से हर राज्य को 1 या 2 या 3 सीटें कुल 36/72/108 सीटें मिलें। वर्तमान संख्या 350 में से बाकी 214 /178/142 सीटें क्षेत्रफल 25%, राजस्व योगदान 25%, मानव विकास सूचकांक 25%, अनुसूचित क्षेत्र/सीमावर्ती 25% के आधार पर बांटी जा सकती है। किसी राज्य विशेष के लिए अधिकतम सीमा 5 सदस्य प्रति राज्य रखी जा सकती। इस से सिक्किम, गोवा, नॉर्थ-ईस्ट की आवाज मजबूत होगी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र को भी जनसंख्या प्रदान की 'सजा' नहीं मिलेगी। हां, यह अवश्य है कि UP, बिहार जैसे राज्यों को लोवा कि उनके प्रदेश का प्रतिनिधित्व घटा।

एक अन्य विकल्प यह हो सकता है कि संविधान संशोधन कर राज्यसभा को योजनाओं पर पूर्ण बहस व सूशोधनों का अधिकार दिया जाए। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधेयक लोकसभा में ही पास होता है। राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है।

संविधान का अनुच्छेद 110 बदले बिना भी राज्य सभा में संसदीय समिति बनाकर को सभी 500 करोड़ से ऊपर की योजनाएं पहले राज्यसभा में विस्तृत बहस के लिए भेजी जा सकती हैं। इस से जिन राज्यों का असर राज्यों पर पड़ता है, उन पर राज्यों के सदन को पूर्व-समीक्षा का अधिकार मिले। इससे संघीय भावना बढ़ेगी। संसामुक्त बंटवारे में जित आयोग की सिफारिश पर राज्यसभा में बहस व समर्थन अनिवार्य हो।

लोकसभा सीटों का राज्यों में वितरण के लिए भी सिर्फ जनसंख्या से हटकर 'बहु-सूचकांक फॉर्मूला' अपनाया जा सकता। यदि केवल जनसंख्या को आधार मानें तो 10,15,20 लाख की जनसंख्या पर एक लोक सभा सीटें निर्धारित हो तो संख्या इस प्रकार हो सकती है:-1420, 940, 720।

एक प्रस्ताव के अनुसार, 2026 के जनसंख्या के आधार पर संविधान में उल्लेखित कुल 543 की सदस्य संख्या का 50% अथवा अन्य कोई प्रतिशत जो संसद तय करे, उसके अनुसार, एक व्यक्ति एक वोट के अनुसार रखी जा सकती है। लोकसभा में 10% प्रतिनिधित्व क्षेत्रफल के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जिस से राजस्थान जैसे बड़े पर कम घनत्व वाले राज्यों का महत्व मिलेगा।

अन्य बिंदु जिन का लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर ध्यान रखा जा सकता है, वे यह हो सकते हैं:- राजस्व एकत्रीकरण:- ---महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु को जोएसटी-आयकर में 15% ज्यादा देते हैं, उन्हें महत्व मिलेगा। विकास व्यय गती:- पिछले 10 साल में पूंजीगत व्यय के आधार पर अर्थात् राज्य में पैसा जमीन पर लगाया उसके आधार पर मानव विकास सूचकांक अर्थात् HDI + पिछड़ापन भी पैमाने में हो। केरल का 3% ऊंचा है तो उसे इनाम मिलना चाहिए। बिहार, झारखंड का कम है

टीवी चैनल पर सामने आए हैं। एक प्रस्ताव है ---राज्यसभा में हर राज्य से 5,7 सांसद हों अर्थात् राज्य सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार न हो। राज्य सभा 'राज्यों का सदन' है। उदाहरणार्थ अमेरिका की सीनेट में हर राज्य से 2 सदस्य होते हैं, चाहे कैलिफोर्निया हो या अलास्का। इससे छोटे राज्यों को संघ में बराबरी मिलती है।

क्या भारत में इस पर, किसी अन्य प्रकार से विचार किया जा सकता है? एक आधार हो सकता है, 250 सीटों में से हर राज्य को 1 या 2 या 3 सीटें कुल 36/72/108 सीटें मिलें। वर्तमान संख्या 350 में से बाकी 214 /178/142 सीटें क्षेत्रफल 25%, राजस्व योगदान 25%, मानव विकास सूचकांक 25%, अनुसूचित क्षेत्र/सीमावर्ती 25% के आधार पर बांटी जा सकती है। किसी राज्य विशेष के लिए अधिकतम सीमा 5 सदस्य प्रति राज्य रखी जा सकती। इस से सिक्किम, गोवा, नॉर्थ-ईस्ट की आवाज मजबूत होगी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र को भी जनसंख्या प्रदान की 'सजा' नहीं मिलेगी। हां, यह अवश्य है कि UP, बिहार जैसे राज्यों को लोवा कि उनके प्रदेश का प्रतिनिधित्व घटा।

एक अन्य विकल्प यह हो सकता है कि संविधान संशोधन कर राज्यसभा को योजनाओं पर पूर्ण बहस व सूशोधनों का अधिकार दिया जाए। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधेयक लोकसभा में ही पास होता है। राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है।

संविधान का अनुच्छेद 110 बदले बिना भी राज्य सभा में संसदीय समिति बनाकर को सभी 500 करोड़ से ऊपर की योजनाएं पहले राज्यसभा में विस्तृत बहस के लिए भेजी जा सकती हैं। इस से जिन राज्यों का असर राज्यों पर पड़ता है, उन पर राज्यों के सदन को पूर्व-समीक्षा का अधिकार मिले। इससे संघीय भावना बढ़ेगी। संसामुक्त बंटवारे में जित आयोग की सिफारिश पर राज्यसभा में बहस व समर्थन अनिवार्य हो।

लोकसभा सीटों का राज्यों में वितरण के लिए भी सिर्फ जनसंख्या से हटकर 'बहु-सूचकांक फॉर्मूला' अपनाया जा सकता। यदि केवल जनसंख्या को आधार मानें तो 10,15,20 लाख की जनसंख्या पर एक लोक सभा सीटें निर्धारित हो तो संख्या इस प्रकार हो सकती है:-1420, 940, 720।

एक प्रस्ताव के अनुसार, 2026 के जनसंख्या के आधार पर संविधान में उल्लेखित कुल 543 की सदस्य संख्या का 50% अथवा अन्य कोई प्रतिशत जो संसद तय करे, उसके अनुसार, एक व्यक्ति एक वोट के अनुसार रखी जा सकती है। लोकसभा में 10% प्रतिनिधित्व क्षेत्रफल के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जिस से राजस्थान जैसे बड़े पर कम घनत्व वाले राज्यों का महत्व मिलेगा।

अन्य बिंदु जिन का लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर ध्यान रखा जा सकता है, वे यह हो सकते हैं:- राजस्व एकत्रीकरण:- ---महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु को जोएसटी-आयकर में 15% ज्यादा देते हैं, उन्हें महत्व मिलेगा। विकास व्यय गती:- पिछले 10 साल में पूंजीगत व्यय के आधार पर अर्थात् राज्य में पैसा जमीन पर लगाया उसके आधार पर मानव विकास सूचकांक अर्थात् HDI + पिछड़ापन भी पैमाने में हो। केरल का 3% ऊंचा है तो उसे इनाम मिलना चाहिए। बिहार, झारखंड का कम है

तो उनको 'हैंड-होल्डिंग' के लिए सीटें बढ़ा कर दी जा सकती है। किस बिंदु को कितना भार देना है, यह संसद तय करे।

सीट कैसे तय हो:--- एक उदाहरण के जरिए हम यों समझे सकते हैं:--कुल 543 सीटें स्थिर रहें। हर राज्य का स्कोर 0.5x जनसंख्या अंश + 0.1x क्षेत्रफल अंश + 0.15 HDI के इंडेक्स के अनुसार +0.15 पिछड़ापन इंडेक्स के अनुसार...अथवा संसद द्वारा तय अन्य किसी अनुपात /लेटज(महत्व, भार) में इन बिंदुओं को ध्यान में रख कर बनाया जाए और संसद से स्वीकृत हो। इस स्कोर पर सीटें बांटी जा सकती है। संतुलन के लिए 3 संवैधानिक सुरक्षा-कवच रखे जा सकते हैं। किसी भी राज्य की 1971 की सीटों से 10/20% से ज्यादा न घटे। इससे दक्षिण को परेशा मिलेगा। राज्यों के अधिकार क्षेत्र की सूची वाले विधेयक राज्यसभा में 2/3 बहुमत से ही पास हों अर्थात् कुछ मामलों में राज्यसभा को एक प्रकार का वीटो मिले।

दक्षिण-नॉर्थ-ईस्ट समूह का गठन किया जाए। लोकसभा-राज्यसभा में 10 से कम सीटें वाले राज्यों का एक वैधानिक 'संसदीय समूह' बने और उसे लोकसभा में एक स्वतंत्र ग्रुप की हैसियत मिले। उसे प्रश्नकाल और अन्य महत्वपूर्ण सवाल पर होने वाली बहसों में उस समूह को समूह की सदस्यों की संख्या के अनुसार अतिरिक्त समय मिले। इसके लिए दक्षिण-नॉर्थ-ईस्ट ग्रुप को विशेष प्रकार की संसदीय अनुमति मिले।

आगे का रास्ता 1. परिसीमन आयोग 2026: इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, लोक सभा और राज्य सभा में पक्ष व प्रति पक्ष अथवा सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता द्वारा नामित एक एक सदस्य, केंद्रीय चुनाव आयोग के एक आयुक्त, नीति आयोग से एक सदस्य, राज्य के मुख्य सचिव आदि इसके सदस्य हों।

2. राष्ट्रीय बहस: 'जनसंख्या बनाम योगदान' पर सभी विधानसभाओं में प्रस्ताव पास कराएँ। 3. संविधान संशोधन: अनुच्छेद 81, 82, 80 में 'बहु-सूचकांक' शब्द जोड़ें। इसके लिए 2/3 बहुमत 2 अथवा राज्यों की सहमति चाहिए।

निष्कर्ष यह माना जा सकता है कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाना और परिसीमन को अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता, पर 'सिर्फ हेड-काट' भारत जैसे संघीय देश में संसदनाक होगा। लोकसभा में 50% भार जनसंख्या को देकर बाकी 50% भार क्षेत्रफल, राजस्व, 3%, पिछड़ेपन को दे दें। राज्यसभा को '1-5 फॉर्मूला' पर लाकर असली 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' बनाएँ और उसे योजनाओं पर बहस, संशोधनों का अधिकार दें।

इससे UP-बिहार को बढ़ा प्रतिनिधित्व भी मिलेगा और तमिलनाडु-केरल को लगेगा कि उनके परिवार नियोजन की मेहनत बेकार नहीं गई। शक्ति संतुलन बचेगा, और संघीय ढांचा मजबूत होगा।

कुछ विद्वानों का यह भी सुझाव है कि निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दों पर बहस ध्यानकर्षण, स्वतंत्र विधेयक प्रस्तुतीकरण आदि के लिए और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके लिए संसद की न्यूनतम अनिवार्य बैठकों के दिन, संख्या संविधान संशोधन कर लाजमी की जाएं। ब्रिटेन की संसद व्यवहारिक रूप से हर साल 100 से 150 दिन बैठके

करती है। फ्रांस में जनता का चुनाव हुआ सदन कमसे कम 120 दिन बैठके करता है। जर्मनी का जनता से चुनाव सदन छुट्टियों को छोड़कर सदैव बैठता है। चीन की नेशनल पीपुल काँग्रेस साल में 1 बार 10 से 14 दिन बैठक करती है। रूस में दो सत्र होते हैं, जनवरी से जुलाई और सितम्बर से दिसंबर की अवधि में।

अजीबो-गरीब तर्क दिए जा रहे हैं, वेणुगोपाल को मु.मंत्री बनाने के लिए

एक तर्क है कि आगामी यूपी चुनाव व 2029 के आम चुनाव की दृष्टि से पार्टी को हिन्दी भाषी संगठन महासचिव चाहिए, अतः वेणुगोपाल को संगठन महासचिव से हटाकर मु.मंत्री बनाकर, केरल भेज देना चाहिए

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 मई। केरल में भारी मतों से जीत के बाद कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चयन करने को लेकर भारी उलझन में है। हर नजरिए से के.सी. वेणुगोपाल इस रस में आगे हैं, क्योंकि उन्होंने टिकटों का वितरण किया है और इस कारण कई विधायकों की कथित वफादारी उनके पक्ष में है। लेकिन ज़मीन पर हकीकत कुछ और ही है।

केरल घर में कांग्रेस के लोग और यहाँ तक कि कांग्रेस के समर्थक और मतदाता के.सी. वेणुगोपाल के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके पोस्टर और पुतले जला

अब, पुराना तर्क है कि विधायकों का बहुमत वेणुगोपाल के पक्ष में है, नहीं दोहराया जा रहा, क्योंकि सभी जानते हैं कि वेणुगोपाल ने केरल में टिकट बाँटे हैं। अतः विधायकों की सतही वफादारी वेणुगोपाल के पक्ष में तो होगी ही।

विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन की टिकट वितरण में कोई भूमिका नहीं थी। अतः सतही तौर पर, सतीशन के पक्ष में बोलने वाले बहुत कम विधायक हैं। पर, सतीशन के सीपीएम सरकार के खिलाफ विधानसभा में पाँच साल तक चलाए गए संघर्षपूर्ण अभियान के लिए विधायकों में बहुत आदर है। अतः अगर सतीशन को मु.मंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस विधायक दल बिखर सकता है।

क्या इस बिखराव का जोखिम उठाकर भी कांग्रेस वेणुगोपाल पर दांव लगाएगी?

सतीशन, रमेश चैन्निथाला, वेणुगोपाल आदि को रविवार को दिल्ली बुलाया गया है तथा पार्टी के समक्ष दुविधा पर मंथन कर, समाधान निकालने की एक बार फिर चेष्टा होगी।

रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ खुला विरोध जता रहे हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

टीवीके के सभी 107 विधायकों ने इस्तीफा देने की धमकी दी थी

क्योंकि डीएमके और अनाद्रमुक के गठबंधन कर सरकार बनाने की कोशिश करने की संभावना उभरी थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 मई। विजय की तमिलनाडु वेनी कजगम (टीवीके) ने चेतावनी दी है कि अगर दो द्रविड़िय पार्टियों में से कोई भी, एम.के. स्टालिन को द्रमुक (टीएमके) या ई. पलानीस्वामी की अनाद्रमुक तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश करने की कोशिश करता है, तो पार्टी के सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे।

यह निर्णय द्रमुक और अनाद्रमुक शिविरों में हुई दो महत्वपूर्ण बैठकों के तुरंत बाद आया। टीवीके को संदेह है कि दोनों पार्टियाँ राज्य में सरकार बनाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं, जिससे वह पार्टी बाहर हो जाए, जिससे जनमत में सबसे अधिक वोट जाए।

टीवीके, जिसने 107 सीटें जीतीं, का कहना है कि अकेली सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, राज्यपाल को उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना

दोनों द्रविड़ दलों के साथ आने की संभावना इसलिए उभरी थी, क्योंकि डीएमके के युवा नेताओ को भय है कि अगर विजय मुख्यमंत्री बन गए तो वे दूसरे एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) साबित होंगे, जिन्होंने एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने जीते जी डीएमके को सत्ता के पास भी नहीं फटकने दिया।

चाहिए।

लेकिन आज सुबह, राज्यपाल आर.वी. अरलेकर ने विजय को सरकार बनाने का दावा पेश करने की अनुमति नहीं दी, यह कहते हुए कि उनके पास आवश्यक संख्या नहीं है। उन्होंने वह योजना भी स्वीकार नहीं की, जो विजय ने बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए प्रस्तुत की थी। सूत्रों के अनुसार, यह बैठक - दो दिनों में दूसरी, राज्यपाल ने इस शर्त पर समाप्त की कि अभिनेता-राजनेता को 118 विधायकों से समर्थन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

राज भवन की एक सूचना में कहा गया कि राज्यपाल ने "तमिलनाडु विधान सभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत समर्थन स्थापित नहीं होने" की बात समझाई। टीवीके को बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए 10 और सीटों की जरूरत है और उसके पास पहले से ही कांग्रेस का समर्थन है, जिसके पांच विधायक हैं। शेष सीटों के लिए लेफ्ट और कुछ छोटी पार्टियों के साथ बातचीत जारी है। सूत्रों ने बताया कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आज 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत

जयपुर, 8 मई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को साल 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर पीठ में एक्टिंग सीजेएसपी शर्मा सुबह 8.30 बजे करेंगे। प्राधिकरण के

मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा शुभारंभ करेंगे।

सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्रि ने बताया कि हाईकोर्ट सहित, सभी अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत के तहत कुल 479 बैचों का गठन किया गया है, जिनमें कुल 7.77 लाख से अधिक मुकदमों को सूचीबद्ध किया गया है। लोक अदालत में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने छात्राओं की माँग तुरंत पूरी की

जयपुर/सीकर, 8 मई। 'बेटी पढ़े, बेटी बड़े' की भावना को साकार करते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को संवेदनशील कार्यशैली का एक अनूठा उदाहरण सामने आया है। जिला सीकर के ब्लॉक खंडेला स्थित जाजोद गांव की बालिकाओं ने रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री से जो माँग रखी, वह आज सुबह होते-होते पूरी हो चुकी थी। गुरुवार को रात्रि चौपाल के दौरान जाजोद गांव की कई छात्राएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलीं और अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने बताया कि उनके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोद में विज्ञान

रात्रि चौपाल में छात्राओं ने विज्ञान संकाय की माँग की, मुख्यमंत्री ने सुबह संकाय खोलने की घोषणा कर दी।

संकाय की सुविधा नहीं है, जिसके कारण उन्हें या तो मजबूरी में अन्य विषयों से पढ़ाई करनी पड़ती है या फिर विज्ञान पढ़ने के लिए घर से काफी दूर जाना पड़ता है। बालिकाओं की बात सुनकर मुख्यमंत्री ने तत्काल उन्हें आश्वासन दिया कि उनके स्कूल में विज्ञान संकाय अवश्य खोला जाएगा। रात को ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। शुक्रवार सुबह जब बालिकाएं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हमारे 300 से अधिक कार्यकर्ता को पीछा करके मारा गया था'

"उस समय शुभेन्दु अधिकारी ने पार्टी को बाँधे रखा था और तुरंत भाग कर वहाँ पहुँचते थे, जहाँ जब भी पार्टी संकट में होती थी"

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 मई। सभी अनिश्चितताओं को दरकिनार करते हुए शुभेन्दु अधिकारी को नव निर्वाचित भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया। इसी बीच, कोलकाता में एक क्रांति चल रही है। न्यू टाउन क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर से दूर, नए मुख्यमंत्री की घोषणा की गई, कोलकाता की ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग, जो कभी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का इंपीरियल सेक्रेटेरियट हुआ करती थी, आज अपने मूल लाल रंग के ऊपर चमक रही है। वर्षों की उपेक्षा और खस्ता हालत के बाद, जब राइटर्स बिल्डिंग वीरान हो गई थी और राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ से शिफ्ट हो गया था, डलहौजी स्क्वायर आज रात एक रहस्यमय आभा बिखेर रहा है, जिसका प्रतिबिंब "लाल दीपी" (मानव निर्मित विशाल तालाब) में नजर आ रहा है।

इस माहौल में शुभेन्दु के अलावा किसी और को मु.मंत्री पद का उम्मीदवार बनाना, पार्टी में भारी निराशा व विरोध पैदा करता।

इस अवसर पर बड़े सोच समझकर, कई पुरानी परम्पराएं पुनः जीवित की गईं। शुभेन्दु अधिकारी के मु.मंत्री बनने की घोषणा ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग से की, जो कभी ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के साम्राज्य का शाही सचिवालय था। बीच में शासन न्यू टाउन एरिया के कन्वेंशन सेंटर से चलाया जाने लगा था, तथा राइटर्स बिल्डिंग वीरान सी पड़ी रहती थी।

आज इस अवसर पर, पुराने स्मरणीय स्थल, जैसे, डलहौजी स्क्वायर, पश्चिम बंगाल के विधानसभा भवन को भगवा रोशनी कर जगमगाया गया था, जो कल तक लाल रंग में डूबा रहता था।

मानो राइटर्स बिल्डिंग से प्रतिस्पर्धा करते हुए, पश्चिम बंगाल विधानसभा भवन, जो कभी इंपीरियल लेजिस्लेचर हुआ करता था, भी केसरिया रंग में नहा रहा है।

और नई सरकार द्वारा सत्ता संभालने से पहले ही, राज्य-स्वामित्व वाले आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में हुई महिला डॉक्टर की मौत की जाँच के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विजय आज शपथ लेंगे तमिलनाडु के मु.मंत्री पद की

अन्ततोगत्वा तमिलनाडु के राज्यपाल को स्वीकार करना पड़ा कि उनकी ज़िद बेबुनियाद थी

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 मई। कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई के समर्थन के साथ बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए, टीवीके प्रमुख विजय ने आज शाम तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अरलेकर ने लंबे समय तक चली अटकलों, अफवाहों और अनिश्चितता को समाप्त करते हुए उन्हें कल सुबह 11 बजे शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है।

इस घटना कुछ ही घंटे पहले जब लेफ्ट पार्टियों ने टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। विजय की पार्टी, जिसने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतीं, पहले सीपीआई, सीपीएम और वीसीके, जो सभी द्रमुक की सहयोगी हैं, से सरकार बनाने के लिए समर्थन मांग

शुक्रवार को राज्यपाल के साथ तीसरी मुलाकात में विजय ने कांग्रेस के अलावा वीसीके, दोनों वामपंथी दलों (सीपीआई और सीपीआईएम) और आईएमएल के समर्थन का प्रमाण पेश किया, जिसके बाद राज्यपाल को उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण देना ही पड़ा।

तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके के 107 विधायक हैं, उसे कांग्रेस के 5, वीसीके के दो, सीपीआई के दो, सीपीआईएम के दो विधायकों का भी समर्थन मिल गया है, इस प्रकार विजय के पास 120 विधायकों का समर्थन है।

विजय को सबसे बड़ी सफलता तब मिली, जब वीसीके ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा की और इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीसीके प्रमुख को मनाया था।

चुकी थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, समर्थन भी प्राप्त हुआ है, जिससे टीवीके को आईएमएल को का गठबंधन का बहुमत 120 सीटों तक

पहुँच गया।

सप्ताह में राज्यपाल के साथ विजय की यह तीसरी मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल के पास अब विजय के दावे को खारिज करने का कोई बहाना नहीं बचा।

टीवीके के एक सूत्र ने बताया कि बैठक के दौरान विजय ने सरकार बनाने के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

संख्या बल अब विजय के पक्ष में है। टीवीके के पास 234-सदस्यीय विधानसभा में 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने पांच विधायकों के साथ समर्थन दिया है। सीपीआई और सीपीएम, जिनके दो-दो विधायक हैं, ने भी आंतरिक बैठकों के बाद टीवीके का समर्थन किया। विद्युथलई चिन्थाइल काच्ची (वीसीके), जिसके पास दो विधायक हैं, ने भी विजय का समर्थन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कनिमोई ने संसद में डीएमके सांसदों के लिए अलग स्थान मांगा

यह अनायास लिया गया निर्णय नहीं है, इसका सबसे मुख्य कारण है, द्रमुक यह नहीं दिखाना चाहती कि उसने कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए हैं, इसलिए कांग्रेस के टीवीके को समर्थन देने पर वह इस प्रकार विरोध जता रही है

पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने इसे अनैतिक कृत्य बताया।

कारार दिया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा की राजनीति तथा महात्मा गांधी की 1925 के उस कथन का अक्षम्य उल्लंघन है कि स्वराज का मतलब नैतिकता पर आधारित सरकार होना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहा कि कांग्रेस ने टीवीके के विजय को अपने साथ जोड़कर अनैतिक कृत्य किया है। मणिशंकर ने कहा, द्रमुक के साथ चुनाव लड़ने के तुरंत बाद उस टीवीके के साथ गठजोड़ करने का फैसला बहुत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 मई। द्रमुक नेता कनिमोई ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर, द्रमुक सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था करने की माँग की। उनकी पार्टी अब कांग्रेस से अलग हो चुकी राजनीतिक गलियारों में इसे केवल संसदीय व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि कहीं अधिक गंभीर राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसका अर्थ 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में गहरी राजनीतिक और वैचारिक दूरी के सार्वजनिक संकेत के रूप में लगाया जा

रहा है।

यह घटना तमिलनाडु में राजनीतिक समीकरणों में तेजी हुए से बदलाव के बीच आई है, जहाँ अभिनेता-राजनेता विजय के उभरने के साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकता के भविष्य को लेकर बढ़ती अनिश्चितता देखी जा रही है। कई वर्षों तक द्रमुक और कांग्रेस मिलकर तमिलनाडु में प्रमुख पार्टी भाजपा धुरी का प्रतिनिधित्व करती रही है। उनका गठजोड़ अक्सर धर्मनिरपेक्ष विपक्षी राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। हालाँकि, संसद में अलग बैठने की माँग अब प्रतीकात्मक रूप से उस सहजता में कमी को दर्शाती है।

कनिमोई ने जिस तरह से यह फैसला लिया है, वह पार्टी में उनके बढ़ते प्रभाव का संकेत है। डीएमके में यही व्यवस्था रही है कि स्टालिन राज्य संभालेंगे और कनिमोई दिल्ली में पार्टी को नेतृत्व देंगी।

अब चूंकि स्टालिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, इसलिए कनिमोई का प्रभाव बढ़ रहा है।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह कदम द्रमुक की बढ़ती चिंता को दर्शाता है, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद तमिलनाडु में नए राजनीतिक समीकरण तलाश रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता राज्य में नए क्षेत्रीय दलों के उभरने और मतदाताओं की बदलती आकांक्षाओं के

बीच द्रमुक पर अपनी दीर्घकालिक निर्भरता का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। संसद में अलग बैठने की माँग को इस बात का संकेत भी माना जा रहा है कि द्रमुक संसद में अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करना चाहती है, विशेष रूप से संघवाद, भाषा राजनीति और प्रस्तावित सीमा-निर्धारण प्रक्रिया

जैसे मुद्दों पर, जहाँ पार्टी ने दक्षिणी राज्यों पर केन्द्रित आक्रामक रुख अपनाया है। दिलचस्प बात यह है कि इस कदम से पहले ही आम चुनावों के बाद कई क्षेत्रीय मतभेदों का सामना कर चुके इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर भी विपक्ष के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन की शुरुआत हो सकती है।

राजनीतिक मजबूरियाँ अंततः राष्ट्रीय विपक्षी एकता को प्रभावित कर सकती हैं। द्रमुक के भीतर भी यह घटना कनिमोई द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय राजनीतिक संदेशों को आकार देने में निभाई जा रही बढ़ती संसदीय भूमिका को उजागर करती है। जहाँ मुख्यमंत्री एम के स्टालिन तमिलनाडु में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कनिमोई दिल्ली में पार्टी की प्रमुख राजनीतिक आवाजों में से एक के रूप में उभर रही हैं।

सतही स्तर पर यह केवल बैठने की एक साधारण पुनर्व्यवस्था दिखाई दे सकती है, लेकिन यह राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन की शुरुआत हो सकती है।

लोग इसमें ममता का राजनीतिक संदेश देख रहे हैं।

भी उनकी पहचान मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज है। इसे लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में ममता बनर्जी के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मुख्यमंत्री शब्द बने रहना केवल तकनीकी चूक नहीं, बल्कि एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीकर के जाजोद में सड़कों पर घूम-घूमकर लोगों से मिले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पी और यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया

सीकर/जयपुर। सीकर के जाजोद गांव में गुरुवार को देर तक रात्रि चौपाल लगाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को सूरज निकलते ही फिर लोगों के बीच पहुंच गए। लोग घरों से निकले तो उन्होंने सड़क पर मुख्यमंत्री को गांव में टहलते हुए पाया। गांव की गलियों में सहजता के साथ भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों, पशुपालकों, फल एवं सब्जी विक्रेताओं तथा युवाओं से संवाद किया और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गांव में स्थित श्री गोपीनाथ जी मंदिर एवं शिव मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों को सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।



सीकर के जाजोद गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घरों में जाकर लोगों से मुलाकात की।

प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि शहरों की ओर पलायन की परिधि बदले और गांव आत्मनिर्भर विकास के सशक्त केंद्र बनें। मुख्यमंत्री ने किसानों से स्थानीय फसलों, कृषि उत्पादों एवं खेती की परंपरिक पद्धतियों के बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें आधुनिक एवं उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीणों के अभाव अभियोगों को गंभीरता से सुनते हुए मुख्यमंत्री ने

अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के कार्यरत पुत्र को सीकर एवं झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पलवाना (सीकर) में निरीक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति देने के आदेश भी तत्काल प्रभाव से जारी करवाए। मुख्यमंत्री ने यमुना जल समझौते को प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह समझौता

वीरगंगा की भावनात्मक अपील पर मुख्यमंत्री ने मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए उनके भीलवाड़ा में कार्यरत पुत्र को सीकर एवं झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पलवाना (सीकर) में निरीक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति देने के आदेश भी तत्काल प्रभाव से जारी करवाए। मुख्यमंत्री ने यमुना जल समझौते को प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह समझौता

■ गांव की गलियों में भ्रमण करते हुये सीएम ने बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों, पशुपालकों, सब्जी विक्रेताओं, युवाओं से संवाद किया

विविध में जल संकट के समाधान तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार में मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है तथा राज्य सरकार विरासत संरक्षण के लिए हवेलियों के जीर्णोद्धार एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीण खासे उत्साहित दिखाई दिए।

ग्रामीणों ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने गांव में रात्रि विश्राम कर आमजन के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को निकटता से समझने और समाधान के प्रयास किए हैं। इस अवसर पर विधायक सुभाष मील और मोहन वरमा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

अलवर : गोविंदगढ़ थाने पर पथराव के चार आरोपियों को जेल भेजा

अलवर, (निसं)। अलवर में थानेदार सहित पुलिसकर्मियों पर पथराव करने वाले चार आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 21 मई तक जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार जिले के गोविंदगढ़ थाने पर छह मई की रात को बुलेट बाइक ज्वल करने पर आरोपियों ने थाने पर हमला किया था। इस हमले में गोविंदगढ़ थाना प्रभारी सहित कई कर्मचारी घायल हुए थे।

एससी/एसटी के सहાયक लोक अभियोजक अधिकारी योगेंद्र खटाना ने बताया कि 7 मई को

■ गोविंदगढ़ थाने पर छह मई की रात को बुलेट बाइक ज्वल करने पर आरोपियों ने हमला किया था

गोविंदगढ़ थाने के एसआई बलबीर जादव की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। छह मई की रात करीब 10:15 बजे एक बुलेट मोटरसाइकिल पटाखे जैसी आवाज करते हुए गुजर रही थी। योगेंद्र खटाना ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान डिटोन (जब्त) कर

लिया। इसी दौरान बाइक चालक के समर्थन में 50-60 लोग थाने पहुंच गए और अचानक पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में थाने के सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और थानाधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान विक्रम सिंह, सुखजित सिंह, अर्जुन सिंह और रौनकी सिंह के रूप में हुई है, जो सभी गोविंदगढ़ के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

युवक की मौत

कोटा, (निसं)। अनंतपुरा थाना इलाके में गलत दिशा से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक सवार काम खत्म करके घर की ओर जा रहा था कि इसी दौरान एक ट्रक रंग साईड से भामाशाह मंडी की तरफ से सीएनजी पम्प की तरफ जाते समय ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल बाइक सवार को उपचार के लिये अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अनंतपुरा थानाधिकारी रमेश कविया ने बताया कि बड़ा बस्ती निवासी सोमू महावर (22) द्यूटी से घर की ओर मोटरसाइकिल से जा रहा था, कि अचानक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी।

टोंक में पांच लाख की अवैध शराब जब्त

टोंक, (निसं)। जिला स्पेशल टीम द्वारा दूनी थाना क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए करीब पांच लाख रुपए की अवैध शराब जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से खरीद-फरोख्त के पांच लाख 24400 रुपए जब्त भी किए गए हैं।

राज्यपाल के अनुसार दूनी थाना क्षेत्र में जिला स्पेशल टीम ने एक दुकान में छाप मारकर दुकान से, 45 पेट्टी अवैध शराब व बोलेरो पुलिस, नादी आदि माल को दूनी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। टीम ने इस दौरान कार्रवाई कर गुस्वारा

रात्रि को दूनी थाना क्षेत्र में स्थित एनएच-52 पर स्थली के पास एक दुकान पर छापामार वहां खड़ी बोलेरो गाड़ी से 15 पेट्टी अंग्रेजी शराब, साथ ही चालक की दुकान से 30 पेट्टी अंग्रेजी व देशी शराब जब्त की गई। इस प्रकार आरोपियों के कब्जे से 45 पेट्टी अवैध अंग्रेजी व देशी शराब की जब्त की गई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग पांच लाख रुपए है। कार्रवाई में आरोपी सुरेश पुत्र देवकर गुर्जर निवासी स्थली और सारवरलाल गुत्र गुवावर्नर गुर्जर निवासी बेनापा थाना दूनी को डिटोन कर दूनी थाने के सुपुर्द कर दिया है।

जोधपुर में शादी समारोह के स्टेज पर आग लगी, वीडियो वायरल

जोधपुर, (कासं)। शहर में एक शादी समारोह के दौरान बरमाला के ठीक समय स्टेज धूँ-धूँ कर जल उठा। पाल रोड स्थित रिसेंट में हुई इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गनीमत रही कि दूल्हा-दुल्हन और वहां मौजूद लोगों ने समय रहते सूझबूझ दिखाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।

वायरल वीडियो के अनुसार स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन बरमाला की रस्म के लिए खड़े थे। इस पल को और शानदार बनाने के लिए स्टेज के चारों तरफ कोल्ड फायर (क्रैकर) चलाए गए और भारी आतिशबाजी की गई। तभी कोल्ड फायर से निकली चिंगारी स्टेज पर सजावट के लिए लगाए गए आर्टिफिशियल (प्लास्टिक) फूलों और

■ बरमाला के दौरान दूल्हा-दुल्हन ने भागकर जान बचाई

कपड़ों पर जा गिरा। इस पर प्लास्टिक के फूलों ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते ही देखते चंद सेकंड में पूरा स्टेज आग की लपटों से घिर गया। जैसे ही स्टेज पर आग भड़की, वहां मौजूद मेहमानों और रिश्तेदारों में चीख-पुकार मच गई। आग की लपटों को अपने करीब आता देखे दूल्हा और दुल्हन ने तुरंत स्टेज से नीचे की तरफ भागकर अपनी जान बचाई। अचानक लगी इस आग से मैरिज गार्डन में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि, वहां मौजूद लोगों ने अग्निशमन उपकरणों व पानी की मदद से आग पर काबू पा लिया।

प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक के लिए प्रवेश 13 मई से

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश के सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक प्रथम वर्ष सत्र 2026-27 के प्रवेश 13 मई से शुरू होंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर (ईसीबी) सहित राज्य के सभी इंजीनियरिंग संस्थानों में इस वर्ष भी प्रवेश के ई-फॉर्म, ऑनलाइन और मेरिट आधारित प्रक्रिया के तहत होंगे। इससे विद्यार्थियों को पारदर्शी तरीके से पसंदीदा कॉलेज और ब्रांच में प्रवेश का अवसर मिलेगा। ईसीबी में आठ ब्रांचों में करीब 600 सीटों पर प्रवेश दिए

■ जेईई मन्स वालों को पहले मौका, ऑनलाइन रिपोर्टिंग से घर बैठे ही सीट कन्फर्म होगी

जाएंगे, जबकि यूसीईटी में लगभग 480 सीटें उपलब्ध रहेंगी। ईसीबी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नवीन शर्मा ने बताया कि सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जयपुर द्वारा संचालित यह प्रक्रिया विद्यार्थियों को सरल और तकनीकी आधारित प्रवेश सुविधा प्रदान करेगी। प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध करवाई गई है। 13 मई से शुरू होने वाली आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को जीएसटी समेत

885 रुपए जमा करवाकर ओटीपी आधारित ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 10 जून निर्धारित की गई है, जबकि आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 जून रहेगी। अभ्यर्थी 26 जून तक कॉलेज और ब्रांच विकल्प भरकर लॉक कर सकेंगे।

प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 12वीं में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है। साथ

ही अभ्यर्थियों ने विज्ञान वर्ग में गणित, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, एप्लीकेशन, बिजनेस स्टडीज, बायोटेक्नॉलॉजी या एंटरप्रेनोरशिप जैसे विषयों के संयोजन के साथ अध्ययन किया होना चाहिए।

डॉ. संजीव जैन, प्राचार्य, ईसीबी का कहना है प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की सहायता के लिए निर्धारित प्रश्न में ऑन लाईन निविदा प्राप्त की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट साईट www.dipr.raajasthan.gov.in/tenders.aspx एवं www.ruvasjaipur.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

संपत्ति के फर्जी दस्तावेज दिखाकर 12 लाख की ठगी

अजमेर, (निसं)। अलवर गेट थाना क्षेत्र में संपत्ति के फर्जी दस्तावेज दिखाकर 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोपी युवक पर विश्वास में लेकर नकली कागजात के आधार पर रकम हड़पने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अलवर गेट थाना क्षेत्र स्थित सेंट जोसेफ स्कूल आनंदपुरी निवासी नवल सिंह ने अलवर गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि एक युवक ने उसे संपत्ति बेचने का झांसा दिया। आरोपी ने खुद को संपत्ति का मालिक बताते हुए संबंधित जमीन और मकान के दस्तावेज दिखाए। दस्तावेज देखने के बाद नवल सिंह ने उस पर भरोसा कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने संपत्ति का सौदा तय कर उससे अलग-अलग किश्तों में करीब 12 लाख रुपए ले लिए। बाद में जब दस्तावेजों की जांच करवाई गई तो वे फर्जी निकले। इसके बाद पीड़ित को अपने साथ हट्टे ठगा का पाता चला।

पावटा : लगन-टीका कार्यक्रम में रस मलाई खाने से करीब 50 लोगों की तबियत बिगड़ी

बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई

पावटा, (निसं)। भाभर क्षेत्र के मालियों की ढाणी, गैसकान में शुक्रवार को दोपहर में आयोजित एक लगन-टीका कार्यक्रम उस समय अफरा-तफरी में बदल गया, जब भोजन के साथ मिठाई के नाम पर परोसी गई रस मलाई

■ भाभर क्षेत्र के मालियों की ढाणी, गैसकान में लगन-टीका कार्यक्रम में भोजन के साथ मिठाई के नाम पर परोसी गई थी रस मलाई

खाने के बाद अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी, जिससे समारोह स्थल पर हड़कंध मच गया। स्थिति गंभीर होने पर परिजनों ने तुरंत मरीजों को आतेला सीएचसी और बाद में शाहपुरा राजकीय उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां एक साथ बड़ी संख्या में मरीज आने से अस्पताल के वार्ड भर गए।

जानकारी के अनुसार करीब 50



लोगों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया।

से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग की चपेट में आए हैं। हालांकि चिकित्सकों की तत्परता से सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा युवा नेता उपेन यादव देर रात शाहपुरा अस्पताल पहुंचे और मरीजों व उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों का हालचाल जाना और परिजनों को ढांडस बंधाते हुए भरोसा दिलाया कि इलाज

में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। यादव ने अस्पताल के पीएमओ डॉ. विनोद योगी एवं चिकित्सा स्टाफ से चर्चा कर सभी मरीजों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। वे करीब दो घंटे तक अस्पताल में मौजूद रहकर मरीजों की स्थिति की जानकारी लेते रहे।

अस्पताल प्रशासन ने भी अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए इमरजेंसी व्यवस्था मजबूत की। मरीजों

के परिजनों ने चिकित्सा टीम और सहयोग में जुटे लोगों की सराहना करते हुए राहत जताई कि समय रहते उपचार मिलने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं क्षेत्रवासियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी परेशानी में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेने की अपील की गई है। वहीं अस्पताल में आने लगे लोगों को चिकित्सकों ने भर्ती कर उपचार शुरू किया।

नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। नाबालिग से छेड़छाड़ के करीब दो साल पुराने मामले में पाँसको क्रम-3 न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

विशेष लोक अभियोजक महेश चांदवानी ने बताया कि 25 मार्च 2024 को नाबालिग 15 वर्षीय पीड़िता ने शहर के एक थाने में रिपोर्ट दी। पीड़िता ने रिपोर्ट में कहा कि घर से सब्जी लेने गई थी, सब्जी की दुकान बंद होने पर पैदल

■ पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर 10 गवाहों के बयान दर्ज कराये

खेतड़ी : मकानों में चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

■ आरोपी से दो लाख रुपए का सामान व 90 हजार रुपए बरामद किये

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी पुलिस ने कस्बे में लगातार हो रही चोरियों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 90 हजार रुपए बरामद किए हैं।

थानाधिकारी मोहनलाल ने बताया कि 12 जनवरी को कस्बे के वार्ड 19 निवासी शीला पांडे ने रिपोर्ट दी कि वह 11 जनवरी को सुबह साढ़े आठ बजे घर के ताला लगाकर जयपुर गई थीं। शाम के समय करीब सात बजे घर पर वापस आईं और मेन गेट का ताला खोलकर मकान में आकर उपर गईं तब देखा दोनों कमरों के ताले टूटे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे टूटे हुए थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने बैट में रखे नकद रुपये व अलमारी में रखे जेवरत चोरी कर लिये तथा कमरों में तोड़फोड़ कर डीवाली भी चोरी कर ले गया। कस्बे में लगातार हो रही चोरियों को लेकर एसपी कावेन्द्र सिंह सागर ने थानाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया तथा पुलिस टीम में पूर्व में खेतड़ी थाने में रहे कांस्टेबल राजवीर सिंह व एचसी चौखाराम को

शामिल किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता से आरोपी सोमवीर ऊर्फ मोटू पुत्र रोहिताशु कुमावत निवासी वार्ड 18 चेलापुड़ी खेतड़ी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब दो लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरत व 90 हजार रुपए नकदी, चोरी किये गये रुपए से खरीदा हुआ कीमती मोबाइल फोन बरामद किया है। थानाधिकारी ने बताया कि चोरी की आरोपी के गहनता से पृथक्ताह की जा रही है। वारदात का खुलासा करने में डीएसटी टीम के कांस्टेबल राजवीर सिंह व एचसी चौखाराम की विशेष भूमिका रही। इस दौरान टीम में थानाधिकारी मोहनलाल, एचसी महेश, पवन कुमार, चौखाराम, कांस्टेबल राजवीर सिंह, अनिल कुमार आदि शामिल रहे।

Rajasthan Medical Services Corporation Ltd.
Gandhi Block, SwasthyaBhawan, Tilak Marg, C Scheme, Jaipur-302005 (Raj.)
Phone No: 0141-2228066, 2228064, WebSite: <http://www.health.rajasthan.gov.in>
E-mail: edpsppmrc@rajasthan.gov.in

No.:- F-8 | RMSC/EPM/M-4/NIB-933/2025-26/RajKaj 22054142 Dated :- 07/05/2026

Corrigendum / Addendum

Corrigendum / Addendum Bid No. (NIB-933) for Item White Sharp Container (White Box) for revised technical specifications has been issued. Corrigendum / Addendum details may be visited on Procurement portal website <https://sppp.raajasthan.gov.in> or www.dipronline.org or <https://eproc.raajasthan.gov.in> or website <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in>.
UBN: MSC2526GLOB00056
Executive Director (EPM) RMSCL
Raj.Samvad/26/2396

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, WATERSHED DEVELOPMENT & SOIL CONSERVATION, PANCHAYAT SAMITI, BARI (DISTT. DHOLPUR)
File no. 101
NOTICE INVITING BID
Date: 05.05.2026

NIT NO 03/2026-27

NIB No. WSC2627A0181 YEAR 026-27

Bids for Construction of Percolation tank with safety wall-03 in PMKSY 2.0 Project area Block Bari Distt Dholpur total estimated value INR 23.88 lacs are invited from interested bidders up to time 06:00 PM Date: 15-05-2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<https://eproc.raajasthan.gov.in>)
UBN: WSC2627WSO08299

(Prem Prakash Marmit)
EXECUTIVE ENGINEER
WATERSHED DEVELOPMENT & SOIL CONSERVATION
P.S. BARI (DISTT DHOLPUR)

DIPRC/8040/2026

OFFICE OF PROJECT MANAGER CUM SUPERINTENDING ENGINEER WATERSHED DEVELOPMENT & SOIL CONSERVATION, DHOLPUR
File no. 240
NOTICE INVITING BID
Date: 05-05-2026

NIT NO. 01/2026-27

NIB No. WSC2627A0183 YEAR 2026-27

Bids for Construction of Retaining wall-3, Tabar renovation-5, Anicut renovation-1, Ped-2 (01 Package) of total estimated value INR 121.21 lacs under PMKSY 2.0 Block Baseri Distt. Dholpur are invited from interested bidders up to time 06:00 PM Date: 15-05-2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<https://eproc.raajasthan.gov.in>)
UBN: WSC2627WSO03001

(Lakhan Singh Meena)
SE/CUM PROJECT MANAGER
WATERSHED DEVELOPMENT & SOIL CONSERVATION DHOLPUR

DIPRC/8064/2026

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड मालपुरा
क्रमांक: 193 दिनांक: 6/5/2026

निविदा सूचना संख्या: 01 / 2026 - 27/खण्ड मालपुरा

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड मालपुरा में सड़क/भवन निर्माण हेतु उपर्युक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संवेदकों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के "ए" एवं "ख" श्रेणी, "सी", "डी" श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हों, से कार्या हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रश्न में प्राप्त की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट साईट www.dipronline.org व www.eproc.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

UBN No.:- PWD2627A0347

1. PWD2627WSRC01530, 2. PWD2627WSRC01531, 3. PWD2627WSRC01532
4. PWD2627WSRC01533, 5. PWD2627WSRC01536, 6. PWD2627WSRC01537
7. PWD2627WSRC01538, 8. PWD2627WSRC01542, 9. PWD2627WSRC01547

DIPRC/8087/2026 अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड मालपुरा

Estate Officer
Rajasthan University of Veterinary and Animal Science (Jobner)
क्रमांक :- EO/RUVAS/2026-27/35 दिनांक :- 05/05/2026

ई-निविदा सूचना संख्या 02/2026-27

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर की ओर से विश्वविद्यालय में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में, इस विश्वविद्यालय में एवं अन्य विश्वविद्यालयों में, राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकृत संवेदकों तथा केन्द्र सरकार व केन्द्र सरकार के अधिकृत संवेदकों को कि राज्य सरकार के उपयुक्त श्रेणी के समकक्ष हों, पंजीकृत संवेदकों से ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रश्न में ऑन लाईन निविदा प्राप्त की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट www.dipr.raajasthan.gov.in/tenders.aspx एवं www.ruvasjaipur.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निविदा आवेदन डाउनलोड करने की तारीख 05.05.2026 सायं 5.00 बजे से

निविदा जमा करने की तारीख 29.05.2026 सायं 5.00 बजे तक

निविदा खोलने की तारीख 30.05.2026 प्रातः 11.00 बजे से

UBN No. :- RVJ2627WSO0800004
सम्पादक अधिकारी

कार्यालय नगर परिषद, झुंझुनू (राज.)
क्रमांक :-स्टोर / 2026 - 27 / 1833 दिनांक :- 07.05.2026

निविदा सूचना संख्या 01 / 2026 - 2027
(NIB Code- DLB2627A1474)
कुल राशि :- 12.80 लाख

नगर परिषद झुंझुनू की ओर से कार्य हेतु सक्षम श्रेणी के पंजीकृत संवेदकों से मोहबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 15.05.2026 दोपहर 1.00 बजे तक निविदा शुल्क जमा करवाकर इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। पूर्णतया भरी हुई निविदाएं दिनांक 15.05.2026 को सांय 2.00 बजे तक वापिस प्राप्त की जाकर उसी तिथि को सांय 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। उक्त निविदा के सम्बन्ध में अधिक जानकारी राजस्थान लोक उपायन पोर्टल (<http://sppp.raj.nic.in>) देखी जा सकती है। कार्य दिवस में कार्यालय में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त नगरपरिषद, झुंझुनू
राज.संवाद/सी/26/2358

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
Corporate Identification Number (CIN) :- U10909RJ2006GCO04842
Registered Office :- Vidhyut Bhawan, Panchsheel Nagar, Makarwadi Road, Ajmer-305004
Office of The Superintending Engineer (Civil)
Email: secivilvvn@gmail.com ; <http://energy.rajasthan.gov.in/ajmer>

No. :- AVVNI/SE/CIVIL/AJM/FC. D :- 217 Date :- 04/05/2026

निविदा सूचना संख्या 01 (2026-27)

केन्द्र / राज्य सरकार के विभागों में 'ए' व 'एए' श्रेणी तथा अ.वि.वि.नि.लि. के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत, अनुभवी तथा माल एवं सेवाकार विभाग से पंजीकृत निविदाकारों से अधिशाषी अभियंता (सिविल / सिविल-QC), अजमेर / उदयपुर / सीकर / चित्तौड़गढ़ के अधीन सिविल कार्यों के लिए निविदाएं UBN No. AVV2627WSO0800005 to AVV2627WSO0800008 आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बंधित समस्त विवरण वेबसाईट <http://sppp.raajasthan.gov.in> व <http://energy.rajasthan.gov.in/ajmer> पर उपलब्ध है।

राज.संवाद/सी/26/2353 अधिशाषी अभियन्ता

नारदापुर विकास प्राधिकरण, नारदापुर
क्रमांक :- सेला/मि.वि.वि. / 01/26/5387 - 98 दिनांक :- 05/05/2026

ऑनलाइन निविदा सूचना सं. 09/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से नारदापुर विकास प्राधिकरण में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रश्न में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से कुल 02 कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

उक्त कार्यों का विस्तृत विवरण, निविदा शर्तें, अनुमानित लागत राशि, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट <http://eproc.raajasthan.gov.in> एवं <http://bhd.raajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन <http://eproc.raajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> पर अवलोकन करें।

UBN विवरण:- WAQ2627WSO0800033, WAQ2627WSO0800034
राज.संवाद/सी/26/2373 अधिशाषी अभियन्ता

‘प्रत्येक प्रगणक एवं पर्यवेक्षक अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ संपादित करें’

बीकानेर, (कासं)। जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत 16 मई से 14 जून तक चलने वाले मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य हेतु नगर निगम के प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के चतुर्थ बैठक का तीन दिवसीय प्रशिक्षण का समापन शुक्रवार को हुआ।

राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण के अंतिम दिन नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलानिचामी एवं उपायुक्त यशपाल आहूजा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए प्रतिभागियों से संवाद किया तथा जनगणना कार्य को गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ संपादित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर आयुक्त सिद्धार्थ ने कहा कि जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके आंकड़े भविष्य की योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का दायित्व है कि वह अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी एवं समर्पण के साथ संपादित करें। अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था एवं प्रतिभागियों की सक्रिय सहभागिता की सराहना भी



बीकानेर में राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में जनगणना प्रथम चरण के चतुर्थ बैठक के प्रशिक्षण को निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलानिचामी ने संबोधित किया।

की। निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलानिचामी ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न फील्ड ट्रेनर्स द्वारा प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को जनगणना कार्य की प्रक्रियाओं, तकनीकी पहलुओं, फील्ड सर्वेक्षण, आंकड़ों के संकलन तथा निर्धारित प्रपत्रों के सही उपयोग संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को

जनगणना कार्य की संवेदनशीलता, शुद्धता एवं समयबद्धता के महत्व से भी अवगत कराया गया। अब पांचवें बैच के प्रशिक्षण का आयोजन 11 से 13 मई तक किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान बीकानेर के मास्टर ट्रेनर डॉ. बाई. बी. माथुर एवं डॉ. विपिन सेनी भी उपस्थित रहे तथा उन्होंने प्रतिभागियों को जनगणना कार्य के विभिन्न पहलुओं की

विस्तार से जानकारी देते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रशिक्षण के अंतिम सत्र में सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों ने सेवा भाव, निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ जनगणना कार्य संपादित करने की शपथ ग्रहण की। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जा रही है। प्रथम चरण

■ प्रशिक्षण में ट्रेनर्स द्वारा प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को जनगणना कार्य की प्रक्रियाओं, तकनीकी पहलुओं, फील्ड सर्वेक्षण, आंकड़ों के संकलन तथा निर्धारित प्रपत्रों के सही उपयोग संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई

के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य वर्ष 2026-27 में संपादित किया जाएगा। जबकि द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना का कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार वर्ष 2027 में किया जाएगा। जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना विकास तथा नीति निर्माण में महत्वपूर्ण आधार के रूप में उपयोग किए जायेंगे।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र का शुभारंभ

देशनोक, (कासं)। राजकीय महाविद्यालय देशनोक में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। यहां रानी लक्ष्मीबाई केन्द्र का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत महिलाओं और बालिकाओं को शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 24 दिवसीय निशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा।

महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. शर्मिला पूनिया ने बताया कि इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए कॉलेज में अध्ययनरत होना अनिवार्य नहीं है। कस्बे की किसी भी स्कूल या कॉलेज की छात्राएं तथा अन्य महिलाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशिक्षण शिविर में विशेषज्ञों द्वारा पंच, किक, ब्लॉक जैसी आत्मरक्षा तकनीकें सिखाई जायेंगी। इसके साथ ही आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेने और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया जाएगा।

प्रशिक्षण शिविर की एक खास विशेषता यह है कि प्रतिभागियों को प्रतिदिन पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर महाविद्यालय की ओर से आधिकारिक प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

सार-समाचार

बच्चों ने चरण धो किया मातृ सम्मान



सुपर किड्स प्रिपरेटरी में बच्चों ने चरण धोकर मातृ सम्मान किया।

बीकानेर, (कासं)। स्थानीय सुपर किड्स प्रिपरेटरी में मदर्स डे बड़े ही उत्साह, प्रेम एवं भावनात्मक वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नन्हे-मुहों बच्चों द्वारा अपनी माताओं का पारंपरिक भारतीय संस्कृति के अद्भुत स्वागत करने के साथ हुई। बच्चों ने माताओं को तिलक लगाकर, चरण धोकर एवं माथा टेककर सम्मान व्यक्त किया, जिसे देखकर उपस्थित सभी अभिभावक भाव-विभोर हो उठे। इस अवसर पर बच्चों ने अपनी माताओं के लिए स्वयं अपने हाथों से आकर्षक कार्ड तैयार किए तथा उनकी कलाई में मदर्स डे ब्रेसलेट पहनकर अपने प्रेम और सम्मान का प्रदर्शन किया। इसके पश्चात बच्चों ने कविता, नृत्य एवं विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से मातृत्व के प्रति अपनी भावनाएँ व्यक्त कीं। नन्हे कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान माताओं के लिए मनोरंजक एवं रोचक खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। विजेता माताओं को सम्मानित कर पुरस्कार प्रदान किए गए। अंत में केक कटिंग एवं मस्तीभरे गतिविधियों के साथ मदर्स डे उत्सव हर्षोल्लासपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सभी माताओं ने सुपर किड्स प्रिपरेटरी परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान में इस प्रकार के सांस्कृतिक एवं रचनात्मक आयोजनों से बच्चों में संस्कार, अत्मविश्वास एवं रचनात्मकता का विकास हो रहा है। माताओं ने प्रिपरेटरी की डायरेक्टर सुप्रिया रावेंचा एवं समस्त शिक्षिकाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम माताओं के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का सुंदर उदाहरण बनकर यादगार रहा।

सम्मेलन के ब्रोशर का विमोचन



वेटरनरी एक्सटेंशन के राष्ट्रीय सम्मेलन के ब्रोशर का विमोचन कुलसूत्र डॉ. सुमंत व्यास ने किया।

बीकानेर, (कासं)। वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर के संघटक वेटरनरी महाविद्यालय, नवनिर्माण (उदयपुर) में वेटरनरी एक्सटेंशन विभाग द्वारा सोसायटी फॉर वेटरनरी एक्सटेंशन का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन 'एक्सटेंशन क्षेत्र की उभरती चुनौतियों के समाधान हेतु पशुचिकित्सा एवं पशुपालन प्रसार सेवाओं का पुनर्विचार' थीम पर 10 एवं 11 सितम्बर को आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय सम्मेलन की ब्रोशर का विमोचन वेटरनरी विश्वविद्यालय के कुलसूत्र डॉ. सुमंत व्यास एवं विश्वविद्यालय की एक्सटेंशन कार्डसिल के सदस्यों द्वारा किया गया। इस अवसर पर संकायाध्यक्ष प्रो. बी.एन. श्रुंगी, कुलसचिव पंकज शर्मा, वित्त निंत्रक विनोद कुमार यादव, निदेशक प्रसार शिक्षा प्रो. राजेश बृद्धिया तथा वेटरनरी महाविद्यालय नवनिर्माण (उदयपुर) के अधिष्ठाता एवं आयोजन समिति अध्यक्ष प्रो. शिव कुमार शर्मा उपस्थित रहे। आयोजन समिति अध्यक्ष प्रो. शिव कुमार शर्मा ने बताया कि यह दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पशुचिकित्सा प्रशिक्षण के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान, व्यावसायिक अनुभवों एवं नवाचारों के आदान-प्रदान का प्रभावी मंच सिद्ध होगी। सम्मेलन में देशभर के लगभग 250 पशुचिकित्सा शिक्षाविद, प्रसार शिक्षा विशेषज्ञ, पशु चिकित्सक, शोधार्थी, विद्यार्थी, उधमी एवं प्रगतिशील पशुपालक भागी लेंगे।

67 पवों सहित गिरफ्तार

नापासर, (कासं)। पुलिस ने भारतमाला रोड स्थित रेस्ट एरिया में कार्रवाई करते हुए युवक को अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बुधवार रात की गई, जहां पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 67 पवें देशी शराब बरामद की। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि नापासर थाना पुलिस की टीम बुधवार रात गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि भारतमाला रोड पर होटल की पार्किंग के पास युवक सफेद कट्टा लेकर खड़ा है और शराब बेचने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सट्टिख युवक से पूछताछ की। तलाशी लेने पर उसके पास रखे कट्टे में देशी शराब के पवें मिले। पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान भूरागम के रूप में हुई है। आरोपी के पास शराब रखने का कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं मिला। पुलिस ने मौके पर वीडियोग्राफी भी कराई। कुल 67 पवें देशी शराब जब्त किए गए, जिनमें से एक पवें को सैल के तौर पर सुरक्षित रखा गया है। नापासर पुलिस ने आरोपी भूरागम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में एएसआई गोकुल चंद मीणा के साथ कांस्टेबल प्रदीप कुमार और वीरेंद्र सिंह भी शामिल थे।

सी.ई.ओ. ने बामनवाली में विकास कार्यों का किया निरीक्षण

बीकानेर, (कासं)। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलजा पांडे ने शुक्रवार को बामनवाली ग्राम पंचायत क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न विकास एवं विकास कार्यों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने पंचायत भवन, मनरेगा एवं एसएफसी मद से विकसित सार्वजनिक पार्क, प्रकाश व्यवस्था, विद्यालय पुस्तकालय तथा ओपन जिम का अवलोकन किया। ग्रामीणों से संवाद करते हुए योजनाओं की उपयोगिता एवं व्यवस्थाओं संबंधी फीडबैक लिया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजना के तहत स्वीकृत कन्वेंशन हॉल एवं मॉडर्न लाइब्रेरी का निरीक्षण किया।

मॉडर्न लाइब्रेरी में उपस्थित बेटियों से संवाद करते हुए उन्होंने शिक्षा, पुस्तक पठन एवं डिजिटल संसाधनों के महत्व पर चर्चा की तथा छात्राओं को नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित किया। राजकीय महाविद्यालय में डीएमएफटी के तहत स्वीकृत हॉल का निरीक्षण किया।



जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलजा पांडे ने बामनवाली में पंचायत भवन, पुस्तकालय का निरीक्षण किया।

इसके बाद उन्होंने श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजना के अंतर्गत विकसित हो रहे भगत सिंह स्टेडियम के कार्यों का जायजा लिया। विधायक निधि से निर्मित सार्वजनिक बस स्टैंड का भी निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। दौर के दौरान उन्होंने क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील का निरीक्षण कर उसके संरक्षण एवं पर्यटन संभावनाओं

पर भी चर्चा की। पंचायत समिति सभागार में आयोजित बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में विकास अधिकारी किशोर कुमार, सहायक अभियंता जगदीश चौधरी, पूर्व प्रधान कानाराम गोयारा, उपायुक्त सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सूने मकान से लाखों की चोरी

बीकानेर, (कासं)। मुक्ताप्रसाद नगर थाना क्षेत्र में सूने मकान से चोर लाखों रूपए चोरी करके ले गए।

पुलिस के अनुसार कांता खतुरिया कॉलोनी निवासी पूनम सिंह सोदा ने मुक्ता प्रसाद नगर थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया गया कि 5 मई को सेक्टर-11 स्थित उनके मकान में चोर घुस गए। बदमाश घर में रखे करीब 100 तोला चांदी के जेवरत और 25 हजार रूपए नकद चोरी कर ले गए।

परिवार के मुताबिक चोरी हुए सामान में पैरों के कड़े, पायल, बिसरी समेत अन्य चांदी के आभूषण शामिल हैं। वारदात का पता उस समय चला जब घर के लोगों ने सामान बिखरा हुआ देखा। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। साथ ही आसपास के संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच एसआई रतनाराम को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

हिस्ट्रीशीटर के अवैध पानी कारोबार पर शिकंजा

बीकानेर, (कासं)। पुलिस अब सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं रहना चाहेगी, बल्कि उनकी अवैध कमाई के नेटवर्क को भी खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस ने जिले के एक हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके अवैध पानी कारोबार पर शिकंजा कसा।

पुलिस ने 34 मुकदमों में नामजद हिस्ट्रीशीटर प्रदीप कुमार नगरासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महाराजा गंगासिंह युनिवर्सिटी के पास चल रहे उसके अवैध पानी स्प्लॉइ नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। आरोपी ने यहां से पुंजर रही पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन कर रखा था और टैकरो के जरिए पानी बेचकर कमाई कर रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस और पीएचईडी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जेलीबी मशीन की मदद से खुदाई कर अवैध पाइपलाइन को काटा गया।

इस दौरान मौके पर भारी पुलिस जाबा तैनात रहा, जिससे इलाके में काफी हलचल रही। कार्रवाई को देखने के लिए आसपास लोगों की भीड़ भी जुट गई। मौके पर पीएचईडी के एईएन

■ पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन कर टैकरो के जरिए पानी बेचकर कमाई कर रहा था

■ पुलिस-पीएचईडी की संयुक्त टीम ने लाइन काटी

योगेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने पूरे नेटवर्क की जांच कर अवैध कनेक्शन हटाने की प्रक्रिया पूरी की। सीओ सिटी अनुज डाल ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अब पुलिस की रणनीति सिर्फ अपराधियों को जेल भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके गैरकानूनी घंघों और अवैध आय के स्रोतों को भी खत्म किया जाएगा। पुलिस ऐसे लोगों की संपत्तियों और अवैध कारोबार की जानकारी जुटाकर लगातार कार्रवाई कर रही है। पूरी कार्रवाई एसपी मृदुल कच्छवा के निर्देशन में की गई।

स्पाॅ सेंटर और कैफे की आड़ में अनैतिक काम

बीकानेर, (कासं)। शहर में स्पाॅ सेंटर और कैफे की आड़ में अनैतिक काम का खेल चल रहा है। कोटगेट थाना क्षेत्र में 4 माह में 13 ठिकानों पर दबिश देकर 50 से ज्यादा युवक-युवतियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

शहर में कोटगेट, कोतवाली, व्यास कॉलोनी, गंगाशहर पुलिस थानों में जगह-जगह स्पाॅ सेंटर और कैफे संचालित किए जा रहे हैं। इनमें बाहर लगे स्पाॅ, मसाज और कैफे के बोर्ड तो केवल नाम के हैं, उन्हें युवतियों से अनैतिक काम कराया जाता है। पिछले तीन-चार सालों में इसका चलन बढ़ गया है।

दूसरे राज्यों और जिलों से युवतियों को यहां बुलाकर इस काम में लगाया जा रहा है। पिछले दिनों पुलिस ने कोटगेट थाना इलाकों में स्पाॅ और कैफे के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई

■ चार माह में 50 से ज्यादा युवक-युवतियां गिरफ्तार

की तो चौंकाते वाले दृश्य सामने आए। इन जगह पर अंदर गुप्त कैबिन और बेड लगे रूम बने हैं जिनमें दूध पाना मुश्किल होता है। दरवाजे इस तरह डिजाइन किए होते हैं कि दीवार की तरह लगते हैं। बाहर कैम्परे भी लगा रखे हैं जिससे पुलिस की गतिविधियों की जानकारी मिल सके। कोटगेट पुलिस ने जनवरी से अब तक रानीबाजार, माडर्न मार्केट, माल गोदाम रोड, केजी कॉम्प्लेक्स के पास सहित स्पाॅ, कैफे के 13 ठिकानों पर दी जहां अनैतिक काम मिला। पुलिस ने इन ठिकानों पर मौके से 50 से ज्यादा युवक-युवतियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया।

रेडक्रॉस सेवाओं पर की चर्चा

बीकानेर, (कासं)। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर शुक्रवार को इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी बीकानेर के तत्वावधान में राजकीय टी.बी वेलीनिक सभागार में रोग नियंत्रण एवं रोकथाम में चिकित्सक, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कार्मिकों एवं विद्यार्थियों की भूमिका विषय पर जिला स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस दौरान मानव सेवा, आपदा राहत और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में स्थानीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय पटल तक रेडक्रॉस के योगदान पर चर्चा हुई।

पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डॉ. बी.सी. धीया ने दीप प्रज्वलन के साथ इसकी शुरुआत की। रेडक्रॉस के मानवीय कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज के दौर में आपदा प्रबंधन, रक्तदान और स्वास्थ्य जागरूकता जैसे क्षेत्रों में यह संगठन अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

शहरी क्षेत्र को बरसाती पानी के ठहराव से मिलेगी मुक्ति

बीकानेर, (कासं)। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बरसाती पानी ठहराव के कारण होने वाली समस्या से आमजन को जल्द ही मुक्ति मिलेगी। इन कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा 59.10 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा कार्यदेश जारी करते हुए विभिन्न स्थानों पर कार्य प्रारम्भ करवा दिए गए हैं।

नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलनीचामी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में बरसाती पानी का ठहराव बड़ी समस्या है। इससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में 100 करोड़ रूपए की लागत से कार्य करवाने की घोषणा की थी। जिसके पहले चरण में 59.10 करोड़ रूपए के कार्यों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा

■ जिला कलेक्टर के निर्देश पर निगम आयुक्त ने किया मौकू मुआयना, 59.10 करोड़ मंजूर

गत दिनों नगर निगम और बीकानेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में इसकी समीक्षा की गई तथा उच्च स्तर पर इससे जुड़ा फीडबैक दिया गया। इसके बाद राज्य सरकार के आपदा नियंत्रण, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा 59.10 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हो गई है तथा 6 मई को तीन स्थानों पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है। निगम आयुक्त ने बताया कि इस

चलती स्कूटी में लगी आग

बीकानेर, (कासं)। शहर के रोशनी घर चौराहे पर शुक्रवार को चलती ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में स्कूटी पूरी तरह आग की चपेट में आ गई।

स्कूटी सवार समय रहते नीचे उतर गया, जिससे वह सुरक्षित बच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने मशकत कर आग बुझाई। घटना के दौरान कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कूटी रोशनी घर चौराहे से गुजर रही थी। इसी दौरान अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग फैल गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण कुछ देर तक वहां ट्रैफिक की आवाजाही भी प्रभावित रही। घटना के बाद एक बार फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हाल के दिनों में तेज गर्मी के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं सामने आती रही हैं।

वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था की

अरजनसर, (निर्सं)। यहां करीब 45 डिग्री तापमान और भीषण गर्मी के बीच क्षेत्र के युवाओं ने गोंवंश और वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था का जिम्मा उठाने की पहल की है। जनसहयोग से प्रतिदिन रोही क्षेत्र में टंकियों के माध्यम से सैकड़ों गोंवंश और वन्य जीवों के लिए पौने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। इन दिनों भीषण गर्मी के कारण रोही क्षेत्र के जोहड़ और तालाब पूरी तरह सूख चुके हैं। पानी के अभाव में वन्य जीव व्यास से बेहाल हो रहे हैं। हिरण, नीलगाय, गोदड़, ऊंट सहित कई वन्य जीव पानी की तलाश में आबादी क्षेत्र की ओर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कुत्तों का खतरा भ्रम रहता है। जैतपुर के सामाजिक कार्यकर्ता भजन यादव ने बताया कि पिछले कई सालों से गर्मी के तौर पर सुरक्षित रखा गया है। नापासर पुलिस ने आरोपी भूरागम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में एएसआई गोकुल चंद मीणा के साथ कांस्टेबल प्रदीप कुमार और वीरेंद्र सिंह भी शामिल थे।

थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों व उनके अभिभावकों को बचाव की जानकारी दी

बीकानेर, (कासं)। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर शुक्रवार को जस्सूर गेट के बाहर डॉ. श्याम अग्रवाल बाल एवं शैलु रोग अस्पताल व अनुसंधान केन्द्र में निःशुल्क जागरूकता एवं जांच शिविर किया गया। शिविर में थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों व उनके अभिभावकों को इस रोग के बचाव के संबंध में परामर्श दिया।

बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. श्याम अग्रवाल ने शिविर में बताया कि भारत में प्रतिवर्ष दस हजार से अधिक बच्चे थैलेसीमिया रोग से पीड़ित पैदा होते हैं। उन्हें पूरी जिन्दगी 15-20 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। रोग से पीड़ित बच्चों का अधिकतर समय अस्पताल में चिकित्सा में ही बीताता है। बच्चा व उनके अभिभावक मानसिक, शारीरिक व आर्थिक परेशानी का सामना करते हैं। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि थैलेसीमिया बीमारी को शत



बीकानेर में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर जागरूकता एवं जांच शिविर में रोगियों की जांच करते डॉ. श्याम अग्रवाल।

प्रतिशत रोक जा सकता है। थैलेसीमिया किस्मत या पूर्व जन्मों के कर्मों की बीमारी नहीं बल्कि जानकारी की कमी

की बीमारी है। अगर दो कैरियर आपस में शादी कर लें तो 25 प्रतिशत खतरा है कि बच्चा ज़िंदगी भर थैलेसीमिया से

तड़पेगा। लेकिन अगर शादी या गर्भधारण से पहले एक जांच करा लें तो हम एक ही पौढ़ी में थैलेसीमिया



सोमलिङ्गं नरो दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते।
लभते फलं मनोवाञ्छितं मृतः स्वर्ग समाश्रयेत्॥

सोमनाथ

विरासत के 75 साल

सोमनाथ भारत की अजेय सभ्यता का प्रतीक है। 1000 वर्षों के विनाशकारी प्रहारों के बाद भी, सोमनाथ आज हमारे आत्म-सम्मान और साहस की मिसाल बनकर खड़ा है। 75 वर्ष पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के संकल्प से आधुनिक सोमनाथ का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, आज यह पावन भूमि भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का उद्घोष कर रही है।

इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बनें

मुख्य गतिविधियां

- कलश यात्रा
- भजन संध्या
- ॐकार मंत्र का जाप
- सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन
- सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन

श्री सोमनाथ मंदिर परिसर, प्रभास पाटन | 8 से 11 मई, 2026

“ सोमनाथ आशा का वह गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है। ”

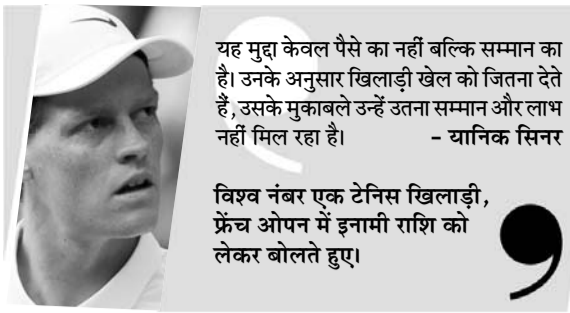
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी (अध्यक्ष, श्री सोमनाथ ट्रस्ट)

सोमनाथ के 1000 साल की गौरवशाली विरासत को और समृद्ध बनाने में योगदान दें।
स्कैन करें।



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान



यह मुद्दा केवल पैसे का नहीं बल्कि सम्मान का है। उनके अनुसार खिलाड़ी खेल को जितना देते हैं, उसके मुकाबले उन्हें उतना सम्मान और लाभ नहीं मिल रहा है।
- यानिक सिनर

विश्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी, फ्रेंच ओपन में इनामी राशि को लेकर बोलते हुए।



खेल जगत

आज का खिलाड़ी



क्रिस्टियानो रोनाल्डो
दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुरुवार को सकूदी प्रो लीग में अपना 100वां गोल दागकर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। रोनाल्डो के गोल की बदौलत अल-नख ने अल-शबाब को 4-2 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर अपनी बढ़त मजबूत कर ली।

क्या आप जानते हैं?... ओलंपिक में व्यक्तिगत रिकॉर्ड : नेविल डिस्सूजा (1956 ओलंपिक में एक मैच में 4 गोल, किसी भारतीय का सबसे बड़ा रिकॉर्ड)।

राष्ट्रदूत बीकानेर, 9 मई, 2026 5

बीसीसीआई एनसीए अंडर-16 ट्रेनिंग कैंप जयपुर में होगा

जयपुर 8 मई। बीसीसीआई के सत्र 2025-26 की राष्ट्रीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले विभिन्न राज्यों के युवा खिलाड़ियों के एनसीए द्वारा आयोजित होने वाले ट्रेनिंग कैंप का आयोजन आरसीए अकादमी, सवाई मान सिंह स्टेडियम में आगामी तारीख 11 जून से 6 जून 2026 के दौरान किया जाएगा। एनसीए ट्रेनिंग कैंप में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के युवा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। स्वर्णव श्रुतिह गुरु दास, अधिवक्ता ईश्वरन, सुकृता जे, के भानु हर्षा, पैला श्याम दिनेश, हार्दिक शर्मा, अनाया नेगी, त्रिनाथ शुक्ला, अभिषेक राजपूत, शिवम मंत्री, ऋषभ सद्के, श्रेयश फडतारे, अद्वैत भट, युवराज सिंह, त्रिप्राणी सामंत, आशुतोष कुमार नाइक, कुव पटेल, अर्नव घोडगावकर, आलोक कुमार, निर्मिक योगेश चारडे, महर्षि प्रीतेशभाई बाघेला, आर्यन त्यागी, विराज माहेस्वरी, नैकज भाटी, शोभा सिंह भाटी। हर्षद खादीवाले बैटिंग कोच, शिब शंकर पॉल बॉलिंग कोच, मंदार साने बॉलिंग कोच, एम. विमलेश फील्डिंग कोच, अभिजीत सिंह सायल फिजियोथेरेपिस्ट, वीरमणि फिजियोथेरेपिस्ट, पूर्णेश शेखर जेना स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, भवनेश कुमार स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, अजिंक्य विनोद सावले परफॉर्मस एनालिस्ट।

मैत्री क्लब ने संस्कार एकेडमी को चार विकेट से हराया

जयपुर, 8 मई। जयपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अनुराग मिश्रा स्मृति बी डिडिजीन लीग में आज खेले गए पूल बी के मैच में मैत्री क्लब ने संस्कार एकेडमी को 4

विकेट से हराया। जी आर ग्रांडर पर संस्कार एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरव कुमार के 111 रन (106 गेंद, 15 चौके व एक छक्का), पारस के 20 रन व खुरशत सिंह के 13 रनों से 43 ओवर में 191 रन बनाए। मैत्री क्लब के लिए हसन खान ने 50 पर 3, मौलिक झरवाल ने 43 पर 2, अरशद, नीतीराज व वरदान ने एक एक विकेट लिया। जवाबी पारी में मैत्री क्लब ने रामदीप के 20 रन, आयुष आमेरिया के 30 रन, वरदान शर्मा के 94 रन व क्षितिज के 23 रनों से 33.3 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन बनाकर मैच जीत लिया। संस्कार एकेडमी के लिए कार्तिक माहेस्वरी ने 34 पर 2, पुलकित माथुर ने 31 पर 2 व प्रणव शर्मा ने 26 पर एक विकेट लिया।

आदित्य टांक की गेंदबाजी से मान क्लब 233 पर सिमटी, खूबेब की फिफ्टी

जयपुर, 8 मई। जयपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित के एम रंगटा टूर्नामेंट के अंतिम आज से खेले गए तीन दिवसीय मैच के पहले दिन टीम सी (मान क्लब) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्मी सैनी के 22 रन, मोहित भगतानी के 20 रन, आदित्य झाला के 23 रन, मोहम्मद खूबेब के 71 रन, चिराग शर्मा के 20 रन व रिहान अली के नाबाद 20 रनों से 60.5 ओवर में 233 रन बनाकर आउट हुई।



आईपीएल 2026 पर 'हनी ट्रैप' का साया, बीसीसीआई का बड़ा एक्शन आईपीएल में अब नहीं चलेगी मनमानी, खिलाड़ियों पर लगेगी लगाम : शुक्ला

नई दिल्ली, 8 मई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को कहा कि शीर्ष क्रिकेट निकाय इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान खिलाड़ियों के लिए नए एक्सेस कंट्रोल नियम लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य अनुशासन को मजबूत करना और टूर्नामेंट प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना है।



लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए शुक्ला ने कहा कि आईपीएल के नए नियम खिलाड़ियों को पहुंच को सीमित करेंगे और होटलों, टीम बसों और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में क्रिकेटर्स के साथ अनधिकृत बैठकों को रोकेंगे। यह कदम पारदर्शिता में सुधार लाने और टूर्नामेंट के दौरान समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष ने कहा कि बीसीसीआई

नए नियम बना रहा है। खिलाड़ियों को पहुंच निर्धारित की जाएगी; आईपीएल की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनधिकृत लोगों को खिलाड़ियों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, न तो होटलों में और न ही बसों में। उनकी यह टिप्पणी बीसीसीआई सचिव देवकीन सैकिया के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा सीजन में खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों और अनधिकृत व्यक्तियों से जुड़ी कई अनियमितताओं के मद्देनजर बोर्ड सभी आईपीएल फ्रैंचाइजी को सख्त सलाह जारी करेगा।

सैकिया ने खुलासा किया कि बीसीसीआई ने स्थापित भ्रष्टाचार-विरोधी और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कई उल्लंघन देखे हैं, जिनमें अनधिकृत व्यक्तियों का

टीम सदस्यों के साथ आना, टीम होटलों में प्रवेश करना और खिलाड़ियों या अधिकारियों के कमरों में घुसना शामिल है। उन्होंने फ्रैंचाइजी मालिकों और अधिकारियों द्वारा खिलाड़ियों से प्रतिबंधित क्षेत्रों में बातचीत करने पर भी चिंता व्यक्त की, जहां आईपीएल नियमों के तहत इस तरह की पहुंच की अनुमति नहीं है। मामले को गंभीर बताते हुए, सैकिया ने कहा कि बीसीसीआई और आईपीएल शासी निकाय टूर्नामेंट प्रोटोकॉल के अनुपालन को मजबूत करने के लिए एक औपचारिक सलाह जारी करेंगे।

उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी उल्लंघन पर बोर्ड द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने आईपीएल में खिलाड़ियों के लिए नए एक्सेस कंट्रोल नियम लागू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ाना है; इन नियमों के तहत होटलों और टीम बसों में अनधिकृत व्यक्तियों को क्रिकेटर्स से मिलने की अनुमति नहीं होगी।

कोलकाता ने दिल्ली को 8 विकेट से हरा लगातार चौथा मैच जीता

एलन का शतक

नई दिल्ली, 8 मई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने फिन एलन की दमदार शतकीय पारी की बदौलत 34 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। कोलकाता ने 14.2 ओवर में दो विकेट पर 147 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। दिल्ली के लिए आशुतोष शर्मा ने सर्वाधिक 39 रन बनाए। इसके जवाब में कोलकाता की शुरुआत खराब रही। टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे रन आउट हुए। अंगकृष रघुवंशी एक रन ही बना पाए। इसके बाद फिन एलन और कैमरन ग्रीन ने विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 64 गेंद में 116 रन की साझेदारी हुई। फिन ने 47 गेंद में नाबाद 100 रन और ग्रीन ने 27 गेंद में 33 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स को केएल राहुल और पथुम निसांका ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी हुई। सलामी बल्लेबाज केएल



राहुल 14 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए। कार्तिक त्यागी ने उन्हें आउट किया। नतीश राणा 8 रन बनाकर ग्रीन का शिकार बने। समीर रिजवी 7 गेंद में तीन रन ही बना सके। ट्रिस्टन स्ट्यूस 4 गेंद में दो रन बनाकर आउट हुए।

एलन-ग्रीन में शतकीय साझेदारी
143 रन का टारगेट चेज कर रही कोलकाता ने 31 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे। कप्तान अजिंक्य रहाणे 13 और अंगकृष रघुवंशी एक रन बनाकर आउट हुए थे। ऐसे में फिन एलन ने कैमरन ग्रीन के साथ शतकीय साझेदारी करके टीम को जीत दिला दी।

11वें ओवर में कोलकाता के फिन एलन ने फिफ्टी पूरी की। उन्होंने मिचेल स्टार्क की पहली बॉल पर छक्का लगाया। इसी छक्के से उनकी फिफ्टी पूरी हुई। इतना ही नहीं, कैमरन ग्रीन के साथ अर्धशतकीय साझेदारी भी हुई।

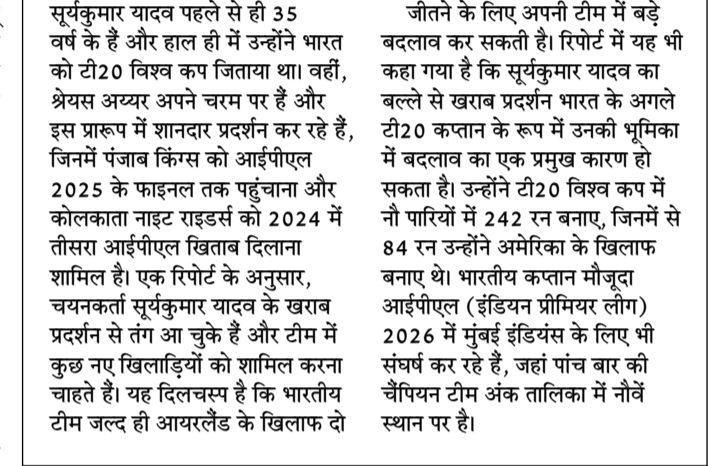
पथुम निसांका ने फिफ्टी लगाई
ओपनर पथुम निसांका ने 29 बॉल पर 50 रन की पारी खेली। जबकि आशुतोष शर्मा ने 39 रन का योगदान दिया। केएल राहुल ने 23 रन बनाए। कोलकाता की ओर से अनुकूल रॉय और कार्तिक त्यागी ने 2-2 विकेट झटके। वैभव अरोड़ा, सुनील नरेन और कैमरन ग्रीन को एक-एक विकेट मिला। एक बैटर रनआउट हुआ।

ग्रीन के छक्के से कोलकाता 100 पार
12वें ओवर में कोलकाता ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। कैमरन ग्रीन ने कुलदीप यादव की तीसरी बॉल छक्का लगाकर टीम को टिपल डिजिट तक पहुंचाया। फिन एलन ने ओवर की पहली बॉल पर छक्का लगाया।

भारतीय टीम में होगा बड़ा बदलाव! सूर्यकुमार की जगह श्रेयस को बनाया जा सकता है कप्तान ?

नई दिल्ली, 8 मई। भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) नेतृत्व में बदलाव की तलाश में है और सूर्यकुमार यादव को भारत के टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान के पद से हटाकर श्रेयस अय्यर को उनकी जगह कप्तान बनाया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि सूर्यकुमार यादव पहले से ही 35 वर्ष के हैं और हाल ही में उन्होंने भारत को टी20 विश्व कप जीता था। वहीं, श्रेयस अय्यर अपने चरम पर हैं और इस प्रारूप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 के फाइनल तक पहुंचाना और कोलकाता नाइट राइडर्स को 2024 में तीसरा आईपीएल खिताब दिलाना शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ता सूर्यकुमार यादव के खराब प्रदर्शन से तंग आ चुके हैं और टीम में कुछ नए खिलाड़ियों को शामिल करना चाहते हैं। यह दिलचस्प है कि भारतीय टीम जल्द ही आयरलैंड के खिलाफ दो

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच होंगे। इस सीरीज में श्रेयस अय्यर टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की कप्तान संभाल सकते हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के मामले में भारतीय टीम का श्रेयलु काफ़ी व्यस्त है। 2028 में होने वाले टी20 विश्व कप और लॉस एंजिल्स ओलंपिक को देखते हुए, भारतीय टीम लगातार तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के लिए अपनी टीम में बड़े बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सूर्यकुमार यादव का बल्ले से खराब प्रदर्शन भारत के अगले टी20 कप्तान के रूप में उनकी भूमिका में बदलाव का एक प्रमुख कारण हो सकता है। उन्होंने टी20 विश्व कप में नौ पारियों में 242 रन बनाए, जिनमें से 84 रन उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बनाए थे। भारतीय कप्तान मौजूदा आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, जहां पांच बार की चैंपियन टीम अंक तालिका में नौवें स्थान पर है।



राजस्थान रॉयल के नए मालिक लक्ष्मी निवास मित्तल ने बेटे के साथ एसएमएस स्टेडियम पर टीम को अभ्यास करते देखा।



राजस्थान रॉयल के नए मालिक लक्ष्मी निवास मित्तल ने बेटे के साथ एसएमएस स्टेडियम पर टीम को अभ्यास करते देखा।

मैग्नस कार्लसन ने अर्जुन एरिगेसी को हराकर 'टेपे सिगैमेन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट 2026' का खिताब जीता

माल्मो, 8 मई। विश्व नंबर-1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने गुरुवार को भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी को सडन डेथ 'प्लेऑफ' में हराकर 'टेपे सिगैमेन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट 2026' का खिताब अपने नाम कर लिया। मुख्य टूर्नामेंट में अपराजित रहने वाले अर्जुन एरिगेसी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन खिताबी मुकाबले में उन्हें मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। टाईब्रेकर की दो बाधियों में दोनों खिलाड़ियों ने एक-एक जीत दर्ज की, जिसके बाद मुकाबला सडन डेथ तक पहुंचा, जहां कार्लसन ने बाजी मार ली।

प्रदेश में पूर्व विधायकों को यथावत मिलती रहेगी पेंशन

राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पूर्व विधायकों को दी जा रही पेंशन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस विनोद कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश मिलाप चंद डांडिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में राजस्थान विधानसभा अधिकारी और सदस्य वेतन, परिलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1956 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विधायकों और सांसदों को मिलने वाले लाभों की संवैधानिक स्थिति लाभग एक समान है। सुप्रीम कोर्ट सांसदों के मामले में पेंशन का मुद्दा पहले ही तय कर चुका है और यह अब अनसुलझा कानूनी प्रश्न नहीं है। अदालत ने

माना की पेंशन केवल पारंपरिक सरकारी सेवा या नियुक्ता व कर्मचारी संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून में कई अन्य श्रेणियों में भी पेंशन को मान्यता दी गई है। अदालत ने कहा कि संविधान के तहत विधान मंडल को पेंशन के संबंध में कानून बनाने की पूर्ण विधायी क्षमता है। संविधान के अनुच्छेद 195 में पेंशन शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता की संविधान में इसे देने पर कोई प्रतिबंध है। इसके अलावा कानून बनाना मुख्य रूप से विधानमंडल का काम है और न्यायिक समीक्षा का दायर विधायी क्षमता की जांच करने तक सीमित है। जनहित याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने साल 1956 के अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 195 केवल वेतन और भत्तों के निर्धारण की शक्ति देता है और इसमें पेंशन का हवाला नहीं है। ऐसे में विधानसभा को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा पेंशन केवल सरकारी सेवा से रिटायर होने पर ही दी जाती है, जबकि विधायक का पद राजनीतिक और संवैधानिक पद है। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लोक प्रहरी के मामले में सांसदों को पेंशन देने का मुद्दा पहले ही तय चुका है। सांसदों और विधायकों की स्थिति एक समान है, इसलिए विधानसभा की ओर से बनाया कानून पूरी तरह वैध है। संविधान भी पेंशन के संबंध में विधानसभा को कानून बनाने की अधिकार देता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

हवामहल के सामने युवती को टक्कर मारने वाला टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार

जयपुर। पुलिस थाना माणक चौक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हवामहल के सामने एक युवती को लापरवाही से टक्कर मार कर घायल करने वाले टैक्सी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हादसे में प्रयुक्त टैक्सी कार को भी बरामद कर लिया है। पुलिस उपायुक्त (जयपुर उत्तर) करण शर्मा ने बताया कि एक युवक ने थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 5 मई की रात जब वह अपने मित्रों के साथ हवा महल राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लोक प्रहरी के मामले में सांसदों को पेंशन देने का मुद्दा पहले ही तय चुका है। सांसदों और विधायकों की स्थिति एक समान है, इसलिए विधानसभा की ओर से बनाया कानून पूरी तरह वैध है। संविधान भी पेंशन के संबंध में विधानसभा को कानून बनाने की अधिकार देता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

कपड़ा फैक्ट्री में करोड़ों रु. का आईपीएल सट्टा पकड़ा

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेंट की स्पेशल टीम (सीएसटी) और मालपुरा गेट थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कपड़ा फैक्ट्री में संचालित अवैध सट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत छह सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर करोड़ों रुपए के हिसाब-किताब घूमने आया था, तब वापस लौटते समय एक वाहन जब्त किए हैं। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त (अपराध) संजीव नैन ने बताया कि पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और विशेष पुलिस अधिष्ठाता (ऑपरेशन) ओमप्रकाश के निर्देशन में सीएसटी ने यह कार्रवाई की। जहां मालपुरा से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मालपुरा गेट इलाके में माल की ढाणी (सांगानेर) स्थित नामग विहार

कॉलोनी के प्लॉट नंबर-3 में संचालित 'चिरायु गव्हित कम्पनी' नामक कपड़ा फैक्ट्री पर दबिश दी। पुलिस ने फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में दबिश देकर आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते उत्तम सैनी (40) निवासी झालाना ग्राम, रूपल बंसल (34) निवासी मुहाना मंडी रोड, राजेंद्र कुमार (46), निवासी पुरानी टोक, देवेंद्र कुमार जंगलानी (37) निवासी मालवीय नगर, विकास नागर (40) निवासी नाहरी का नाका और मनोहर स्वामी (38) निवासी बाबाजी की ढाणी, सांगानेर को गिरफ्तार किया। पुलिस और वह जेल भी लाए गए और बंगलुरु के बीच खेले जा रहे आईपीएल मैच पर आरोपियों द्वारा दांव लगाए जा रहे थे। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपित मालवीय नगर के बड़े बुकी अशोक गुप्ता और बाबू उर्फ नैनी से सट्टे की लाइन लेकर जूम एफ के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी

का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी लंबे समय से कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बुकी उत्तम सैनी और फैक्ट्री मालिक मनोहर इस कारोबार में बराबर के पार्टनर थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 डॉंगल, चार्जर केबल, कैलकुलेटर, सट्टे के हिसाब-किताब से जुड़े 6 रजिस्टर तथा 1540 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा एक लगजरी स्कॉर्पियो, होंडा डियो स्कूटी, एक्टिवा स्कूटी और पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीएसटी के एसआई संदीप बसेरा, एसएसआई कनल डामर गुप्ता और बाबू उर्फ नैनी से सट्टे की लाइन लेकर जूम एफ के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी लंबे समय से कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बुकी उत्तम सैनी और फैक्ट्री मालिक मनोहर इस कारोबार में बराबर के पार्टनर थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 डॉंगल, चार्जर केबल, कैलकुलेटर, सट्टे के हिसाब-किताब से जुड़े 6 रजिस्टर तथा 1540 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा एक लगजरी स्कॉर्पियो, होंडा डियो स्कूटी, एक्टिवा स्कूटी और पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीएसटी के एसआई संदीप बसेरा, एसएसआई कनल डामर गुप्ता और बाबू उर्फ नैनी से सट्टे की लाइन लेकर जूम एफ के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी लंबे समय से कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बुकी उत्तम सैनी और फैक्ट्री मालिक मनोहर इस कारोबार में बराबर के पार्टनर थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 डॉंगल, चार्जर केबल, कैलकुलेटर, सट्टे के हिसाब-किताब से जुड़े 6 रजिस्टर तथा 1540 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा एक लगजरी स्कॉर्पियो, होंडा डियो स्कूटी, एक्टिवा स्कूटी और पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीएसटी के एसआई संदीप बसेरा, एसएसआई कनल डामर गुप्ता और बाबू उर्फ नैनी से सट्टे की लाइन लेकर जूम एफ के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी लंबे समय से कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बुकी उत्तम सैनी और फैक्ट्री मालिक मनोहर इस कारोबार में बराबर के पार्टनर थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 डॉंगल, चार्जर केबल, कैलकुलेटर, सट्टे के हिसाब-किताब से जुड़े 6 रजिस्टर तथा 1540 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा एक लगजरी स्कॉर्पियो, होंडा डियो स्कूटी, एक्टिवा स्कूटी और पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीएसटी के एसआई संदीप बसेरा, एसएसआई कनल डामर गुप्ता और बाबू उर्फ नैनी से सट्टे की लाइन लेकर जूम एफ के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी लंबे समय से कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बुकी उत्तम सैनी और फैक्ट्री मालिक मनोहर इस कारोबार में बराबर के पार्टनर थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 डॉंगल, चार्जर केबल, कैलकुलेटर, सट्टे के हिसाब-किताब से जुड़े 6 रजिस्टर तथा 1540 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा एक लगजरी स्कॉर्पियो, होंडा डियो स्कूटी, एक्टिवा स्कूटी और पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीएसटी के एसआई संदीप बसेरा, एसएसआई कनल डामर गुप्ता और बाबू उर्फ नैनी से सट्टे की लाइन लेकर जूम एफ के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी लंबे समय से कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बुकी उत्तम सैनी और फैक्ट्री मालिक मनोहर इस कारोबार में बराबर के पार्टनर थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 डॉंगल, चार्जर केबल, कैलकुलेटर, सट्टे के हिसाब-किताब से जुड़े 6 रजिस्टर तथा 1540 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा एक लगजरी स्कॉर्पियो, होंडा डियो स्कूटी, एक्टिवा स्कूटी और पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीएसटी के एसआई संदीप बसेरा, एसएसआई कनल डामर गुप्ता और बाबू उर्फ नैनी से सट्टे की लाइन लेकर जूम एफ के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी लंबे समय से कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बुकी उत्तम सैनी और फैक्ट्री मालिक मनोहर इस कारोबार में बराबर के पार्टनर थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 डॉंगल, चार्जर केबल, कैलकुलेटर, सट्टे के हिसाब-किताब से जुड़े 6 रजिस्टर तथा 1540 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा एक लगजरी स्कॉर्पियो, होंडा डियो स्कूटी, एक्टिवा स्कूटी और पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीएसटी के एसआई संदीप बसेरा, एसएसआई कनल डामर गुप्ता और बाबू उर्फ नैनी से सट्टे की लाइन लेकर जूम एफ के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी लंबे समय से कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बुकी उत्तम सैनी और फैक्ट्री मालिक मनोहर इस कारोबार में बराबर के पार्टनर थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 डॉंगल, चार्जर केबल, कैलकुलेटर, सट्टे के हिसाब-किताब से जुड़े 6 रजिस्टर तथा 1540 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा एक लगजरी स्कॉर्पियो, होंडा डियो स्कूटी, एक्टिवा स्कूटी और पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीएसटी के एसआई संदीप बसेरा, एसएसआई कनल डामर गुप्ता और बाबू उर्फ नैनी से सट्टे की लाइन लेकर जूम एफ के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी लंबे समय से कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बुकी उत्तम सैनी और फैक्ट्री मालिक मनोहर इस कारोबार में बराबर के पार्टनर थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 डॉंगल, चार्जर केबल, कैलकुलेटर, सट्टे के हिसाब-किताब से जुड़े 6 रजिस्टर तथा 1540 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा एक लगजरी स्कॉर्पियो, होंडा डियो स्कूटी, एक्टिवा स्कूटी और पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीएसटी के एसआई संदीप बसेरा, एसएसआई कनल डामर गुप्ता और बाबू उर्फ नैनी से सट्टे की लाइन लेकर जूम एफ के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी लंबे समय से कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बुकी उत्तम सैनी और फैक्ट्री मालिक मनोहर इस कारोबार में बराबर के पार्टनर थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 डॉंगल, चार्जर केबल, कैलकुलेटर, सट्टे के हिसाब-किताब से जुड़े 6 रजिस्टर तथा 1540 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा एक लगजरी स्कॉर्पियो, होंडा डियो स्कूटी, एक्टिवा स्कूटी और पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीएसटी के एसआई संदीप बसेरा, एसएसआई कनल डामर गुप्ता और बाबू उर्फ नैनी से सट्टे की लाइन लेकर जूम एफ के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी लंबे समय से कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बुकी उत्तम सैनी और फैक्ट्री मालिक मनोहर इस कारोबार में बराबर के पार्टनर थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 डॉंगल, चार्जर केबल, कैलकुलेटर, सट्टे के हिसाब-किताब से जुड़े 6 रजिस्टर तथा 1540 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा एक लगजरी स्कॉर्पियो, होंडा डियो स्कूटी, एक्टिवा स्कूटी और पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीएसटी के एसआई संदीप बसेरा, एसएसआई कनल डामर गुप्ता और बाबू उर्फ नैनी से सट्टे की लाइन लेकर जूम एफ के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी लंबे समय से कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बुकी उत्तम सैनी और फैक्ट्री मालिक मनोहर इस कारोबार में बराबर के पार्टनर थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 डॉंगल, चार्जर केबल, कैलकुलेटर, सट्टे के हिसाब-किताब से जुड़े 6 रजिस्टर तथा 1540 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा एक लगजरी स्कॉर्पियो, होंडा डियो स्कूटी, एक्टिवा स्कूटी और पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीएसटी के एसआई संदीप बसेरा, एसएसआई कनल डामर गुप्ता और बाबू उर्फ नैनी से सट्टे की लाइन लेकर जूम एफ के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी लंबे समय से कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस जांच में यह

हैदराबाद में 200 करोड़ रूपए के फूड पार्क, सीड एवं फूड प्रोसेसिंग के एमओयू

मुख्यमंत्री भजनलाल ने हैदराबाद में ग्राम-2026 के तहत इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित किया

हैदराबाद/जयपुर, 8 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर एग्रीटेक एवं फूड प्रोसेसिंग के सुनहरे अवसरों की भूमि बन चुका है। कृषि पैदावार में विविधता के कारण राजस्थान में प्रसंस्करण उद्योग, कोल्ड चेन, स्पाइस पार्क एवं कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार प्रदेश को कृषि आधारित उद्योगों और वैल्यू एडेड

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान प्रदेश को कृषि आधारित उद्योगों और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का वैश्विक केन्द्र बनाने की दिशा में प्रयासरत है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित किया।

विभिन्न स्थानों पर फूड पार्क, सीड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न एमओयू का आदान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में वन-टू-वन बिजनेस मीटिंग्स एवं निवेशकों, उद्योग जगत और एग्रीटेक विशेषज्ञों के साथ संवाद किया गया।

इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्योगिकी मंजू राजपाल, आईसीआरआईएसएटी के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक, फिक्की नेशनल एग्रीकल्चर कमेटी के सह-अध्यक्ष सुब्रतो गीस सहित, कृषि विभाग,

राजस्थान फार्मेशन के हैदराबाद चैंप्टर स्टार्टअप उद्यमी एवं निवेशक के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

टीवीके के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पाटी कोट जाने की योजना बना रही है। द्रमुक ने शुक्रवार को एक बैठक की, जिसमें चार प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें से एक प्रस्ताव पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन को "आपातकालीन निर्णय लेने" का अधिकार देता है। प्रस्ताव के बारे में द्रमुक ने कहा, "हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक और चुनाव को टाला जाए, एक स्थिर सरकार बनाई जाए और साम्प्रदायिक ताकतों को कोई मौका न दिया जाए।" बहुमत की कमी को "जटिल संकट" बताते हुए, द्रमुक ने अपने सभी विधायकों से कहा है कि वे 10 मई तक चेन्नई में रहें। हालांकि, द्रमुक के शीर्ष सूत्रों ने पुष्टि की कि एक योजना पर विचार किया जा रहा है, जिसमें ई. पलानीस्वामी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और द्रमुक बाहर से समर्थन देगा। द्रमुक के कुछ युवा नेताओं, विशेषकर उदयनिधि स्टालिन के शिबिर को डर है कि विजय सत्ता में आने के बाद एम.जी. रामचंद्रन की तरह हो जाएंगे और उन्हें हटाना लगभग असंभव होगा। विख्यात एमजीआर ने जीवन भर द्रमुक को सत्ता से बाहर रखा था। पार्टी के पुराने नेता, जिनमें एमके स्टालिन शामिल हैं, अभी भी पूरी तरह अस्वस्थ नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार, वे इस प्रयोग पर जनता की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि यह दो पार्टियों का साझा प्रयास है, जो दशकों से आमने-सामने रही है, और उन्हें भारी विरोध का डर है। अन्नाद्रमुक ने भी इसी तरह का कदम उठाया है, जिसने अपने विधायकों से कहा है कि वे प्रतीक्षा करें और देखें।

'हमारे 300 से अधिक कार्यकर्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिए आयोग स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ममता बनर्जी को पिछली सरकार के कुछ कार्यों की जांच के लिए भी एक आयोग स्थापित किया जा रहा है। पूरी तरह से जांच शुरू हो गई है और शुभेन्द्र अधिकारी के व्यक्तिगत सहायक के हत्यारों की तलाश शुरू हो गई है, जिनकी हत्या एक दिन पहले राजनीतिक कारणों से की गई थी। नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों द्वारा कल कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कम से कम बीस भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में शपथ ली जाएगी। दुर्भाग्यवश, अपनी असभ्यता जारी रखते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समारोह में भाग नहीं लेंगी। इससे पहले सभी सेवानिवृत्त मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते रहे हैं। वेसे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, ममता बनर्जी "पूर्व" शब्द जोड़ने का बजाय अब भी खुद को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। शुभेन्द्र को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करने की घोषणा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम कोलकाता में की, जब नव निर्वाचित विधायकों का एक सम्मेलन संपन्न हुआ। भाजपा संसदीय बोर्ड ने अमित शाह को विधायकों की बैठकों की अध्यक्षता करने और नेता व मुख्यमंत्री चुनने का कार्य सौंपा था। गृह मंत्री ने सदन के नेता

और मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित नाम आमंत्रित किया था, जिस पर नव निर्वाचित विधायकों ने एकमत होकर शुभेन्द्र अधिकारी का नाम ज़ोर से पुकारा। जब अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा की, तब विधायकों ने कोई अन्य वैकल्पिक नाम नहीं दिया। लेकिन शुभेन्द्र की इस शानदार जीत पर एक दुख की छाया भी थी, क्योंकि उनके युवा कार्यकारी सहायक, जो भारतीय वायुसेना के पूर्व कर्मचारी थे, की एक दिन पहले राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। भावुक अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से शोक व्यक्त किया कि उनके पी.ए. को भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र (ममता बनर्जी के गढ़) में उनकी जीत का मूल्य चुकाना पड़ा। मौजूदा हालात में कोई और विकल्प अकल्पनीय होता। अधिकारी ने 2021 से लगातार सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी थी। इस मोड़ पर शुभेन्द्र को छोड़कर किसी अन्य उम्मीदवार को चुनने से पार्टी के पहले कदम को ही बाधित कर सकता था। पार्टी कार्यकर्ताओं की सत्ताधारी दल द्वारा लगातार और बेरहम तरीके से प्रताड़ित किया गया। भाजपा का दावा है कि पार्टी के कम से कम 300 ग्राउंड-लेवल कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया और मारा गया, जबकि कई अन्य को प्रताड़ना और हत्या से बचने के लिए अपने घर छोड़ने पड़े। शुभेन्द्र ने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा और

जहां भी पार्टी संकट में थी, वे स्वयं वहाँ पहुंचे। शुभेन्द्र स्वयं हमेशा खतरे में रहे। पार्टी अब नई शुरुआत और राज्य के लोगों की उम्मीदों की दहलीज़ पर है।

मुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्कूल जाते समय मुख्यमंत्री से एक बार फिर मिलीं और अपनी मांग दोहराई, तो मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए बताया कि जाजोद के स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू हो चुका है। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इस विद्यालय में आप गणित एवं जीव विज्ञान दोनों में से अपनी रुचि अनुसार विषय चुनकर इसी साल से पढ़ाई कर सकती हैं। मुख्यमंत्री के मुंह से खुशखबरी सुनकर बच्चियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा कि उनकी मांग इतनी जल्दी पूरी होगी।

ममता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजनीतिक संदेश भी माना जा सकता है। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सुनिश्चित सुरक्षा, संरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करने के 11 वर्ष का जश्न

अब तक लगभग 95 करोड़ संयुक्त नामांकन के साथ असुरक्षितों को सुरक्षा कवच

भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज

2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64% हुआ - 45% की वृद्धि - आईएलओ

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

किफायती जीवन बीमा कवर
₹436 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर

27+ करोड़ से अधिक नामांकन

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

दुर्घटना बीमा कवर
₹20 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹2 लाख का आकस्मिक मृत्यु एवं दिव्यांगता बीमा कवर

58+ करोड़ से अधिक नामांकन

Atal Pension Yojana

गारंटीड मासिक पेंशन
60 वर्ष की आयु के बाद
₹1,000-₹5,000 तक की सुनिश्चित पेंशन

9+ करोड़ से अधिक नामांकन

व्यापक पात्रता

18-50 वर्ष आयु के वे व्यक्ति जिनका बैंक या डाकघर में खाता है

आसान नामांकन एवं नवीनीकरण

बैंक/डाकघरों के माध्यम से सरल पंजीकरण तथा वार्षिक ऑटो-डेबिट सुविधा



समावेशी पात्रता

18-70 वर्ष आयु के वे व्यक्ति जिनका बैंक या डाकघर में खाता है

कम लागत एवं आसान नवीनीकरण

सिर्फ ₹20 वार्षिक प्रीमियम के साथ ऑटो-डेबिट नवीनीकरण सुविधा



समावेशी सामाजिक सुरक्षा योजना

18-40 वर्ष आयु के गैर-आयकरदाता बैंक खाताधारकों के लिए खुली

सुरक्षित बचत

सरकार समर्थित पेंशन आभवासन के साथ लचीला अंशदान



विजय आज शपथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने की सहमति दी। शुक्रवार को चेन्नई में बातचीत हुई, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यक्तिगत रूप से वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन से बात कर टीवीके नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थन को सुनिश्चित किया। इसके तुरंत बाद, सीपीआई कार्य समिति और सीपीएम की राज्य नेतृत्व टीम ने भी विजय का समर्थन किया, जिससे अगले सरकार बनाने को लेकर अनिश्चितता समाप्त होने की संभावना बढ़ गई। राज्यपाल और विजय ने बुधवार और गुरुवार को भी मुलाकात की थी। दोनों बार अरलेकर ने विजय के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि टीवीके नेता के पास विधानसभा में आवश्यक समर्थन नहीं है। लोक भवन ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि "सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन" स्थापित नहीं हुआ है। इस निर्णय के बाद टीवीके कार्यकर्ताओं ने राज भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन

किया, जबकि कांग्रेस ने राज्यभर में राज्यपाल और केन्द्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की। गुरुवार को अरलेकर के निर्णय के जवाब में, कांग्रेस नेता गिरीश चौडणकर ने कहा कि राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना ही चाहिए। उन्होंने मीडिया से कहा कि बहुमत का परीक्षण केवल विधानसभा के पटल पर किया जा सकता है। उन्होंने भाजपा एवं आरएसएस पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया, जबकि भाजपा के पास विधानसभा में केवल एक विधायक है। तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंधर्ग ने 8 मई को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की अपील की, आरोप लगाते हुए कि राज्यपाल संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और टीवीके को सरकार बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में, विजय ने सीपीआई राज्य मुख्यालय का दौरा कर नेताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

अजीबो-गरीब तर्क ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन के प्रति भारी और व्यापक समर्थन है, जिन्होंने पिछले पांच सालों में लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ संघर्ष का लगातार नेतृत्व किया। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "सतीशन के लिए पूर्ण समर्थन है, और अगर नेतृत्व के.सी. वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाता है, तो इतनी बड़ी फूट और मजबूत मतभेदों के बीच वे पार्टी, सरकार और राज्य नहीं चला पाएंगे।" सभी प्रमुख हितधारकों, जिनमें वी.डी. सतीशन, रमेश चेन्नीथला, वेणुगोपाल और अन्य शामिल हैं, को दिल्ली बुलाया गया है और कल एक बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि इस मुद्दे पर चर्चा हो और पूरी प्रक्रिया में समझदारी लाई जा सके। वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पूरी ताकत

लगा दी है। पिछले 9 वर्षों से वे संगठन के प्रभारी एआईसीसी महासचिव रहे हैं और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। जो लोग वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि आने वाले साल में उत्तर प्रदेश चुनाव और 2029 के आम चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी को संगठन प्रभारी के रूप में हिंदी भाषी क्षेत्र के हिंदी बोलने वाले व्यक्ति की जरूरत है, ताकि यह साबित किया जा सके कि संगठन को कुर्सी पर नया नेतृत्व चाहिए और केरल को के.सी. वेणुगोपाल की जरूरत है। सियासी खींचतान जारी है और पार्टी का केरल संगठन और एआईसीसी इस मुद्दे पर पूरी तरह विभाजित है। पार्टी की एकता बिखरी हुई है और आज केरल कांग्रेस गंभीर रूप से विभाजित है।

रेजिडेंसियल स्कूल में निर्माण के लिये 800 साल पुराना मंदिर तोड़ा

हैदराबाद, 08 मई। तेलंगाना के वारंगल जिले में एक यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंसियल स्कूल के निर्माण के लिए 800 साल पुराने काकतीय कालीन शिव मंदिर को बुलडोजर से ढहा दिया गया, जिससे आक्रोश और कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। खानपुर मंडल के अशोक नगर में हुई इस घटना पर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएचए) में शिकायत के बाद केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय और पुरातत्व विभाग ने मामला दर्ज कर लिया है। वकील इम्मनेनी रामा राव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि काकतीय शासक गणपति देव (1199-1262 ईस्वी) के शासनकाल के इस शिव मंदिर को खानपुर मंडल में यंग इंडिया

इंटीग्रेटेड रेजिडेंसियल स्कूल के निर्माण के लिए भारी मशीनों से नष्ट कर दिया गया। शिकायत में कहा गया कि अधिकारियों ने तेलंगाना हेरिटेज एक्ट के तहत अनिवार्य विरासत संरक्षण समिति का गठन नहीं किया।

टीवीके ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खराब है, जिसने 23 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को हराया। अच्यर ने कहा, कांग्रेस ने पांच सीटें जीतीं, उसने ये सीटें अपने दम पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से द्रमुक के साथ अपनी दशकों पुरानी कनिष्ठ साझेदारी के बल पर जीतीं।

"जन सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से हम सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में किसी भी गरीब व्यक्ति को संकट के समय अपने परिवार के भविष्य की चिंता न करनी पड़े।"

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी



हमें फॉलो करें | [f](#) [t](#) [i](#) [x](#) [i](#) [n](#) [g](#) | [financialservices.gov.in](#)